राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण बुधवार 11अगस्त-2021 वर्ष-4, अंक - 199 पृष्ठ-08 मूल्य-01रुपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बांबे हाईकोर्ट में नए आईटी कानूनों पर तुरंत रोक लगाने की गुहार

मुंबई। नया सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमावली 2021 अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसर की तरह है क्योंकि इसका नियम अस्पष्ट, दमनकारी और कठोर है। नए आईटी कानून के प्रावधानों के खिलाफ मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट में दलील दी गई और नए नियम के कार्यान्वयन पर तुंरत रोक लगाने का आग्रह किया गया। बांबे हाईकोर्ट में दो याचिकाकर्ताओं ने नए आईटी कानूनों को चुनौती दी है। समाचार पोर्टल द लीफलेट और पत्रकार निखिल वागले ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि आईटी नियमों का प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर घातक असर पड़ेगा। द लीफलेट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ से नए नियमों के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नए नियमों में नागरिकों, पत्रकारों, डिजिटल समाचार पोर्टलों द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित सामग्री पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सामग्री के नियमन और उत्तरदायित्व की मांग करना ऐसे मापदंडों पर आधारित है जो अस्पष्ट हैं और वर्तमान आईटी नियमों के प्रावधानों तथा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परे हैं। खम्बाटा ने कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सामग्री पर खुलकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यह नियम आईटी कानून के मापदंडों से परे जाते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाबदेही और शिकायत निवारण का भी प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सामग्री को विनियमित करने और जवाबदेही की मांग का आधार उन मापदंडों पर आधारित है जो अस्पष्ट हैं और मौजूदा आईटी अधिनियम के प्रावधानों और अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से परे है।

राहुल की अनुपस्थिति में सिब्बल के घर जुटे विपक्षी दलों के बड़े नेता, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार रात एक डिनर की मेजबानी की, जिसमें विपक्षी पार्टी और समान विचारधारा वाले दलों के राजनीतिक दिग्गजों ने भाग लिया। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।इस डिनर बैठक में 15 पार्टियों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे और सभी नेताओं ने सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ-साथ एक मजबूत मोर्चा बनाने पर भी चर्चा की। बता दें कि सिब्बल सोनिया गांधी को व्यापक सुधारों के लिए लिखे गए पत्र के पीछे प्रमुख प्रस्तावक थे और उन्हें उन नेताओं में से एक भी देखा जाता है जिनके राहुल गांधी के कामकाज से गंभीर मतभेद हैं। वहीं अब इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी में ही चर्चा होने लगी है कि क्या इस तरह से बैठक बुलाना सही था। हालांकि डिनर में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं ने किसी भी अटकलों को खारिज कर दिया कि यह पार्टी के आंतरिक कामकाज से संबंधित था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे 2024 के चुनावों से पहले मजबूत विपक्षी एकता चाहते हैं।गौरतलब है कि 'जी-23' के नाम से मशहूर हुए कांग्रेसी नेता पार्टी में ब्लॉक से लेकर सीडब्ल्यूसी स्तर तक के चुनाव चाहते थे और इस संबंध में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। जो जी-23 नेता रात्रिभोज में शामिल हुए, उनमें मेजबान सिब्बल के अलावा गुलाम नबी आजाद, भूपिंदर सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, मनीष तिवारी और शशि थरूर शामिल थे। भोज में आमंत्रित विपक्ष के एक नेता ने बताया कि एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकें और आयोजित की जानी चाहिए। हमें भाजपा को 2022 में पहले उत्तर प्रदेश में और फिर 2024 के आम चुनाव में हराना है। सूत्रों ने बताया कि सिब्बल की शुरुआती टिप्पणी के बाद सभी नेताओं ने कहा कि उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश में और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए एक साथ आना होगा।

जेल से निकलने के बाद लालू पहली बार सामूहिक बैठक में शामिल हुए

वहीं तबीयत में कुछ सुधार होने के बाद लालू यादव भी इस सामूहिक डिनर में पहुंचे थे। इस मौके पर लालू यादव ने भी सिब्बल की बातों से सहमति जताते हुए विपक्षी एकता को मजबूत करने पर बल देने को कहा। उन्होंने कहा कि हम जब भी मुश्किल में आते हैं सिब्बल साहेब को याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के अनुभव का फायदा उठाए।

इन नेताओं ने लिया भाग-इस दौरान राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के लालू प्रसाद यादव, राकांपा सुप्रीमो शरद पवार, समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी. राजा, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम भी मौजूद थे। शिवसेना के संजय राउत, आप के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन, बीजद नेता पिनाकी मिश्रा और अमर पटनायक, द्रमुक के तिरुचि शिवा और टी के एलनगोवन, रालोद के जयंत चौधरी और टीआरएस के नेता भी रात्रिभोज में शामिल हुए।

आज भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी

पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीआइआइ की वार्षिक बैठक11 और 12 अगस्त यानी दो दिन आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में सरकार के कई मंत्री वरिष्ठ अधिकारी शिक्षाविद और भारतीय उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

● प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक का विषय भारत के 75 साल आत्मानिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसायी मिलकर कर रहे हैं काम रखा गया है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीआइआइ की वार्षिक बैठक 11 और 12 अगस्त यानी दो दिन आयोजित की जाएगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 4:30 बजे आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक का विषय भारत के 75 साल आत्मानिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसायी मिलकर कर रहे हैं काम रखा गया है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीआइआइ की वार्षिक बैठक 11 और 12 अगस्त यानी दो दिन आयोजित की जाएगी।

इस कार्यक्रम के विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि अध्यक्ष के रूप में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री व आर्थिक नीतियों के समन्वय मंत्री हेंग स्वी कीट रहेंगे। इस आयोजन में सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

बुधवार को होने वाली वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी भारत में व्यवसाय और उत्पाद बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं, साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बीच सोमवार को वाणिज्य सचिव बीवी आर सुब्रमण्यम ने सोमवार को सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के विस्तार की वकालत की है।

दिल्ली वालों को आज से घर बैठे मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं

इस सेवा के शुरू होने से आवेदकों को वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र, लर्निंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। केवल फिटनेस टेस्ट और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एमएलओ जाना पड़ेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली में अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित वाहनों से संबंधित दस्तावेज के लिए आवेदकों को मोटर लाइसेंसिंग दफ्तर (एमएलओ) जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 अगस्त को परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं की शुरुआत करेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा, इस सुविधा के शुरू होने से दफ्तरों में भीड़भाड़ और इंतजार से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां परिवहन संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री आईपी एस्टेट एमएलओ से सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। सराय काले खां और वसंत विहार

कार्यालयों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का ट्रायल चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

न्यायिक व्यवस्था को ठप किया तो सरकार का प्रशासन भी होगा बाधित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों को लेकर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जजों की नियुक्ति नहीं करके केंद्र ने लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ (न्यायपालिका) को ठप कर दिया है, अगर यहीं रवैया जारी रहा तो प्रशासनिक कामकाज भी बाधित हो जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, सरकारी अथॉरिटी को यह समझना चाहिए कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपने हद पार कर दी है। अगर आप न्यायिक व्यवस्था को ठप करना चाहते हैं तो आपकी व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को रुकने नहीं दे सकते। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से कहा, न्यायाधीशों की भारी कमी है, लेकिन आप इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। समय आ गया है कि आप इसे महसूस

करें। जजों की नियुक्ति नहीं होती है तो अहम मामलों का जल्द निपटारा भी लगभग असंभव हो जाएगा। पीठ एंटी डंपिंग शुल्क मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस एनवी रमण ने शुक्रवार को ही न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों में देरी पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। चीफ जस्टिस ने तो सरकार से यह सवाल भी किया था कि वह ट्रिब्यूनल को जारी रखना चाहती है या बंद करना चाहती है।

अड़ियल रवैया अपना रहा केंद्र-शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति मामले में सरकार के अड़ियल रवैये पर सख्त नाराजगी दिखाई। कहा, कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद नियुक्ति नहीं हो रही है, जबकि न्यायिक आदेश के जरिये इसके लिए समयसीमा भी तय की गई है। इस पर माधवी दीवान ने कहा कि एंटी-डंपिंग के विशेषज्ञ निकाय के समक्ष देरी का कारण हाईकोर्ट में लंबित मामला हो सकता है। लेकिन पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया।

भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी अब लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। कोरोना से सुरक्षा देने के लिए देश में टीकाकरण चल रहा है, अभी तक सिर्फ 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिकों को ही वैक्सीन लगवाने की इजाजत थी लेकिन अब भारत में रह रहे विदेश नागरिक भी टीका लगवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा कर यह जानकारी दी थी। भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने के लिए, विदेशी नागरिकों को पहचान के प्रमाण के रूप में अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद सरकार के CoWIN प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराना होगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद, उन्हें टीकाकरण के लिए एक स्लॉट मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रह रहे हैं, विशेष रूप से बड़े महानगरीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में, कोविड -19 के फैलने की संभावना अधिक है। ऐसी किसी भी घटना की संभावना का मुकाबला करने के लिए, यह जरूरी है कि सभी लोगों को कोरोन की वैक्सीन लगाई जाए। सरकार के मुताबिक, यह पहल विदेशी नागरिकों को कोविड से बचाने के साथ-साथ भारत में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए भी है, यह पहल भारतीय लोगों में वायरस फैलने की संभावनाओं को भी कम करेगी। भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए वायरस से समग्र सुरक्षा की दिशा में यह एक अच्छा कदम होगा। भारत का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम जनवरी 2021 से संचालित हो रहा है। अब तक देश भर में 51 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक टीकाकरण के पात्र हैं।

वैज्ञानिकों ने निकाला सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला, कोरोना के हर वेरिएंट पर करेगा प्रहार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से परेशान दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला खोजा है जो कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने कोरोना को मात दे चुके लोगों में ऐसी एंटीबॉजी खोजी है जो हर तरह से वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। यह अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में पांच मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर शोध का वर्णन किया गया है। यह बीटा वेरिएंट पर

प्रभावी पाया गया। शोधकर्ताओं ने इस दौरान कोरोना से ठीक हुए लोगों में विशिष्ट मेमोरी बी कोशिकाओं की जांच की। मेमोरी बी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये उन वायरस को पहचानती हैं और उनके खिलाफ प्रतिक्रिया देती हैं जो पहले शरीर पर हमला कर चुका होता है।

स्टेम हेलिक्स नामक संरचना को करते हैं टारगेट

वैज्ञानिकों ने कोरोना को हरा चुके लोगों में मिली पांच एंटीबॉडी में से एस2पी6 पर ध्यान देना शुरू किया। आणविक संरचना विश्लेषण और कार्यात्मक अध्ययनों से पता चला है कि इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में प्रभावशाली विविधता थी। साथ ही यह कोरोना के बीटा वायरस के तीन अलग-अलग उपजातियों को बेअसर कर सकता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसा उसने कोशिका झिल्लियों के साथ जुड़ने की वायरस की क्षमता को बाधित करके किया। ये एंटीबॉडी इन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में स्टेम हेलिक्स नामक संरचना को लक्षित करते हैं। स्पाइक प्रोटीन मेजबान कोशिकाओं पर कब्जा करने की वायरस की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या होता है स्पाइक प्रोटीन?

कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर कांटों की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, वहां से वायरस प्रोटीन निकलता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण शुरू होता है। यह इंसान के एंजाइम एसीई2 रिसेप्टर से जुड़ फेफड़ों में पहुंचता है। फिर संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ाता है।

'सत्ता के सानिध्य' में तैयार हुई विरोध की रणनीति, अब पैदल चलेंगे कार्यकर्ता

नई दिल्ली। 'सानिध्य' सत्ता का हो और 'तैयारी' विरोध की। और तैयारी भी कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि पार्टी का सुपर लीडर कराए तो उस तैयारी से निकलने वाला हर योद्धा मैदान में मास्टर स्ट्रोक लगाने को तैयार ही होता है। कुछ इसी अंदाज में जब कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने जब छत्तीसगढ़ में 'सत्ता के सानिध्य' में उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को यूपी में विरोधी लहर के बीच विरोध करने का मंत्र दिया था, तभी तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।

कांग्रेस कार्यकर्ता अब आगामी विधानसभा चुनाव तक रोजाना न सिर्फ पैदल मार्च करेंगे बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर

● उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की योजना है कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ दो दिन में नहीं खत्म होने वाला। कांग्रेसी नेताओं का कहना है आने वाले विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता खासतौर से मास्टर ट्रेनर और उसके सात प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता गांव में और शहर शहर में भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की पोल भी खोलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था

में जाकर वोटर से मिलकर सत्ता पक्ष की नाकामियों की पोल भी खोलेंगे।

इसी कड़ी में अगस्त क्रांति पर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे प्रदेश में किसानों की बदहाली, बदहाल कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा से गद्दी छोड़ो मार्च का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हर विधानसभा में पांच किलोमीटर की पदयात्रा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा दो दिन की यह पदयात्रा मंगलवार को भी जारी रहेगी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो प्रशिक्षण कांग्रेसी नेताओं को दिया था उसी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति पर यह विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में जो मास्टर ट्रेनर को तैयार करने की बात कही गई थी वह सारे मास्टर ट्रेनर अगस्त क्रांति मार्च में भी मौजूद रहे। योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को पहले चरण में सत्तर हजार से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार करने थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक यह सत्तर हजार मास्टर ट्रेनर अगले हफ्ते में तैयार हो जाएंगे और उसके बाद इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की योजना है कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ दो दिन में नहीं खत्म होने वाला। कांग्रेसी नेताओं का कहना है आने वाले विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता खासतौर से मास्टर ट्रेनर और उसके सात प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता गांव में और शहर शहर में भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की पोल भी खोलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था और उनको विरोध में और ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रखने की बात कही थी।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

पिछड़ों के लिए एकजुट

ओबीसी आरक्षण विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एकजुटता गौरतलब है। पिछले दिनों से पार्टियों को परस्पर दो-दो हाथ करते ही देखा जा रहा था, लेकिन भारत में आरक्षण का महत्व इतना ज्यादा हो गया है कि कोई पार्टी इसके विरोध में दिखना कतई पसंद नहीं करेगी। हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक को चर्चा के बाद पारित करने की बात कही है, लेकिन सत्ता पक्ष को शायद विपक्ष पर कम विश्वास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के सांसदों के लिए तीन लाइन का एक व्हिप जारी किया है। व्हिप में पार्टी सांसदों से 10 और 11 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों से भी सदन में उपस्थित रहने की अपील की है। इससे ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक के महत्व को समझा जा सकता है। सवाल कई हैं, क्या सदन में चर्चा के बाद भी सहमति बनी रहेगी? क्या इस आरक्षण में किसी अन्य संशोधन की मांग विपक्ष करेगा? क्या ओबीसी आरक्षण पर किसी पार्टी की कोई अलग मंशा सामने आएगी? खैर, इन सवालों का जवाब सदन में ही मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि पक्ष और विपक्ष के बीच बनी सहमति भी संदेह से परे नहीं है। निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आगे बढ़कर कहा कि आज सभी विपक्षी दलों ने बैठक की है और निर्णय लिया है कि उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में हर विधेयक पर चर्चा होना अच्छी बात है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को भी बिना बहस पारित होते देखा है, जिससे देश को जमीनी स्तर पर परिणाम और विश्वास का नुकसान भी हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित विधेयक का पारित होना जरूरी है। केंद्र सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि वह राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे रही है। अभी तक यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास था, लेकिन विगत वर्षों से राज्यों ने भी अपनी जरूरत के हिसाब से ओबीसी सूची को अंजाम दिया है। अभी 5 मई को ही मराठा आरक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार नहीं है। अब केंद्र सरकार चाहती, तो इस अधिकार को अपने पास रख सकती थी, पर स्थानीय जरूरतों को देखते हुए अगर केंद्र सरकार ने राज्यों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, तो स्वागत है। वैसे आगे की राह आसान नहीं होगी और एक राज्य की देखा-देखी, दूसरे राज्यों में भी आरक्षण की मांग उठेगी। जाति आधारित आरक्षण में अगर एकरूपता नहीं होगी, तो जाति आधारित राजनीति को ही बल मिलेगा। इस संविधान संशोधन से जहां राजनीति का विस्तार होगा, वहीं दबंग जातियों का स्थानीय स्तर पर वर्चस्व भी बढ़ जाएगा। यही वह मोर्चा है, जहां राजनीतिक दलों को सावधान रहना चाहिए। आरक्षण के लिए बार-बार संविधान बदलने से ज्यादा जरूरी है कि पिछड़ी जातियों को पूरी तेजी के साथ आगे लाया जाए, उनके कल्याण के लिए सियासत से ऊपर उठकर तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं।

'आज के ट्वीट

आवश्यकता

देश की 136 करोड़ आबादी किसी भी प्रकार के जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर केवल एक धर्म, 'राष्ट्र-धर्म' के साथ जुड़ी है। सभी भारतीय अगर अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू कर दें तो भारत महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा। दुनिया को इस बात का अहसास कराने की आवश्यकता है। - योगी आदित्यनाथ

नीरज चोपड़ा का मतलब सोने पर सुहागा

- आरके सिन्हा

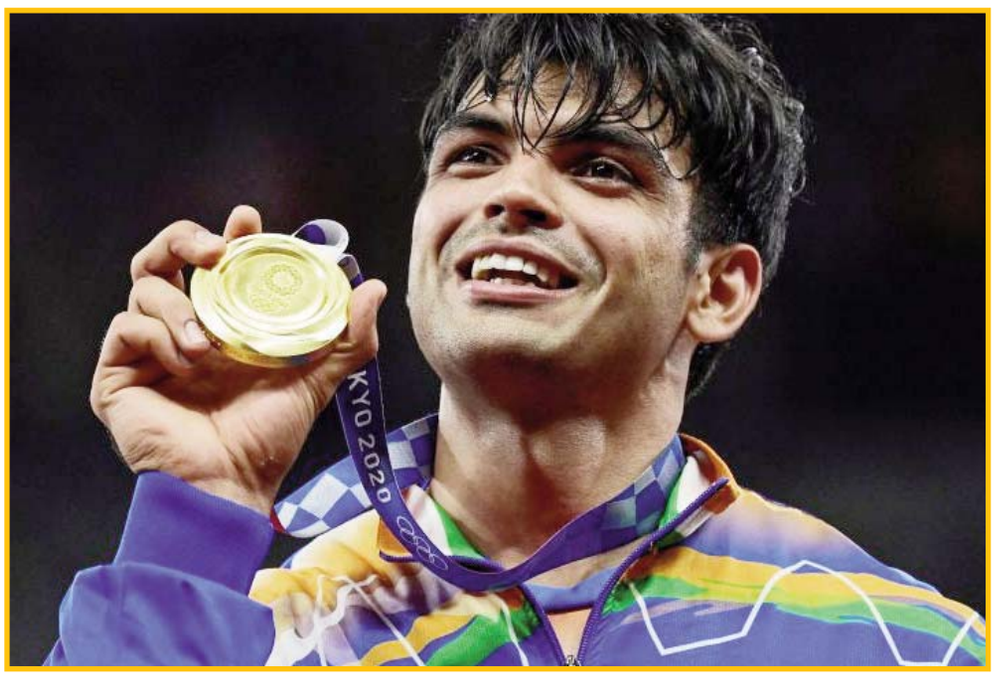

ओलम्पिक खेलों में एथलेटिक्स को अव्वल स्थान प्राप्त है। शुरुआत के कुछ दशकों में ओलंपिक में एथलेटिक्स या फील्ड एंड ट्रैक प्रतियोगितायें ही छाई रही थी। बाद में इन खेलों को भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि खेलों की जननी है एथलेटिक्स। लेकिन, उसी एथलेटिक्स में भारत के हिस्से में ओलंपिक खेलों में कभी कोई महान सफलता नहीं आई थी। लेकिन, टोक्यो ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो (भाला फेंक प्रतियोगिता) में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया कि भारत के खिलाड़ी एथलेटिक्स में भी दमखम रखते हैं। वे अब अपने हिस्से के आकाश को छूने के लिए तैयार हैं। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले ही अपनी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हां, मिल्खा सिंह, गुरुबचन सिंह रंधावा, श्रीराम सिंह, पीटी उषा तथा अंजू बॉबी जार्ज जैसे धावकों ने भारत को एशियाई खेलों से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में कुछ पदक और सफलताएं दिलवाईं थी। पर ये सभी ओलंपिक खेलों में पदक पाने से चूक गए थे। उस कमी को अब नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। सच में नीरज चोपड़ा ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। गोल्ड मेडल जीतने के जश्न के दौरान नीरज चोपड़ा ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि तिरंगे को ससम्मान सही ढंग से समेटा जाए। इन छोटी- छोटी बातों से उनके व्यक्तित्व का अंदाजा होता है। नीरज चोपड़ा ने यह जो गोल्ड मेडल देश को दिलवाया है, उसे जीतने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की होगी या कितना पसीना बहाया होगा, यह अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सारा देश अब करीब से जानने लगा है और अपना हीरो मानने लगा है । उन्होंने देश को स्वर्णिम क्षण देकर सच में बहुत ही बड़ा उपकार किया। कोरोना की दो लहरों से जूझते देश को मानो उन्होंने और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले बाकी खिलाड़ियों ने नई पीढ़ी को संजीवनी दे दी है। भारत इनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। जब नीरज चोपड़ा के हमउम्र लाखों नौजवान उम्र-जनित भावनाओं के वशीभूत हो कर तफ़रीह, ऐशो-आराम में डूबे होंगे तब नीरज चोपड़ा और अन्य ओलंपिक पदक विजेतागण कड़ी धूप, बारिश और सर्दी में सूर्योदय से शाम तक मैदान पर पसीना बहा रहे होंगे। उन्होंने कई अवरोधों का भी सामना किया होगा। पर उन्होंने न सिर्फ़ अपने मनोबल को बरकरार रखा, बल्कि अपने लक्ष्य को भी कभी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों के इतिहास में ट्रेक एंड फील्ड में भारत का पहला गोल्ड मेडल हासिल कर हरेक भारतीय को गौरवान्वित किया है। उनकी यह उपलब्धि देश के लिए अमूल्य और ऐतिहासिक है। ऐसे पल हमारे नसीब में अबतक बहुत कम ही आये हैं। नीरज चोपड़ा ने जब टोक्यो में जेवलिन हाथ में लिया तब अपनी मेहनत पर यकीन और भरोसा उनके चेहरे पर अंकित था। इस भरोसे ने देश की उम्मीदों को भी परवान चढ़ा दिया और उन्होंने अपने 130 करोड़ हमवतनों को मायूस नहीं किया। उन्होंने देश की झोली उम्मीदों से भी ज्यादा भरकर दे दी। नीरज चोपड़ा अब मिल्खा सिंह और श्रीराम सिंह की तरह भारतीय सेना के एक और शानदार खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा अभीतक सूबेदार हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें सेना में प्रोन्नत किया जायेगा और कोई बेहतर पद मिलेगा। भारतीय सेना ने अभीतक उनकी ट्रेनिंग आदि के लिए भरपूर निवेश भी किया है। वे पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीच्यूट में ट्रेनिंग करते रहे हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब कुछ बातें भविष्य में होती नजर आ रही हैं। पहली तो यह कि अब हमारे धावकों के सामने नीरज चोपड़ा का उदाहरण होगा कि अगर वे ओलंपिक में पदक ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इससे देशभर के लाखों नौजवान एथलेटिक्स में आएँगे। वे मेहनत करेंगे और ओलंपिक खेलों में मेडल लाने की हर चंद कोशिश करेंगे। उन्हें सफलता भी मिलेगी। दूसरी संभावना यह भी लग रही है कि अब देशभर के युवाओं का एथलेटिक्स के प्रति आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा। नौजवान इस खेल को भी अब अपने करियर के रूप में लेंगे। याद रख लें कि खेलों में करियर बनाना कोई घाटे का सौदा नहीं रह गया है। आप जैसे ही एक मुकाम को छूते हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी तो मिल ही जाती है। उसके बाद धन और दूसरी सुविधाएं भी खिलाड़ियों को मिलने ही लगती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विज्ञापनों से भी मोटी कमाई होने लगती है। नीरज चोपड़ा को तो सेना, उनके राज्य, केन्द्र सरकार और दूसरी जगहों से कुल जमा 20 करोड़ रुपये तक तो मिल जाएगा पुरस्कार की शक्ल में। इसके अलावा वे विज्ञापनों से भी खूब कमा सकेंगे। उनके लिए अब भारत भी सब कुछ देने को तैयार है। हालांकि किसी भी नौजवान को अपने करियर के शुरू में यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे फलां-फलां पदक जीतने पर कितना धन मिलेगा। खिलाड़ी को लक्ष्य तो सिर्फ शिखर पर जाने का होना चाहिए। देखिए, मुझे कहने दें कि हमारे यहां सुविधाओं का बहुत रोना रोया जाता है। कहने वाले तो यह कहते हैं कि सुविधाओं के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। अगर उन्हें सुविधाएं मिलती तो वह कुछ और जौहर दिखाते। इस बार के ओलंपिक खेलों में अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, इथोपिया और युगांडा के भी बहुत से धावकों ने अपने देशों को कई-कई गोल्ड मेडल जितवाए हैं। क्या इन अफ्रीकी देशों में खिलाड़ियों को भारत से अधिक सुविधाएं मिलती है? कतई नहीं। हमारे देश के कम से कम 100 शहरों में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे का विकसित हो चुका है। खेलों में या जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में कामयाबी तो तब ही मिलती है, जब आप में सफल होने का जुनून पैदा हो जाता है। एक बार महान धावक श्रीराम सिंह बता रहे थे कि हमारे अधितकर खिलाड़ी नौकरी मिलने के बाद सोचते हैं कि उन्हें जीवन में सबकुछ मिल गया। वे फिर शांत हो जाते हैं। श्रेष्ठ खिलाड़ी वही होता है जो बार-बार सफल होता है। सारी दुनिया जमैका के धावक और आठ बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बोल्ट को इसलिए मानती है, क्योंकि वे बार-बार ओलंपिक खेलों में सफल होते थे। वे 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4म100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकार्डधारी हैं। इन सभी तीन दौड़ों का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के नाम है। 1984 में कार्ल लुईस के बाद 2008 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में बोल्ट एक ओलंपिक में तीनों दौड़ जीतने वाले और एक ओलंपिक में ही तीनों दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके साथ ही 2008 में वे 100 और 200 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक खिताब पाने वाले भी पहले व्यक्ति बने। नीरज चोपड़ा का आदर्श बोल्ट होने चाहिए। उनका अगला लक्ष्य 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना होना चाहिए। और अंत में एक बात और ! यह पहली बाद ऐसा हुआ है कि देश ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते। इसमें एक बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी और उनके दो मंत्रियों पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी दिया जाना चाहिये, जिन्होंने समय निकालकर खिलाड़ियों का भरपूर प्रोत्साहन किया और उनका मनोबल बढ़ाया।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

ज्ञान गंगा

मानसिक स्वच्छता

श्रीराम शर्मा आचार्य/ मन की चाल दोमुंही है। जिस प्रकार दोमुंही सांप कभी आगे, कभी पीछे चलता है, उसी प्रकार मन में दो परस्पर विरोधी वृत्तियां काम करती रहती हैं। उनमें से किसे प्रोत्साहन दिया जाए और किसे रोका जाए, यह कार्य विवेक बुद्धि का है। हमें बारीकी के साथ यह देखना होगा कि इस समय हमारे मन की गति किस दिशा में है? यदि सही दिशा में प्रगति हो रही हैं, तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए और यदि दिशा गलत है, तो उसे पूरी शक्ति के साथ रोका जाए, इसी में बुद्धिमत्ता है। क्योंकि सही दिशा में चलता हुआ मन जहां हमारे लिए श्रेयस्कर परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, वहां कुमार्ग पर चलते रहने से एक दिन दुःखदायी दुर्दिन का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते चेत जाना ही उचित है। उचित दिशा में चलता हुआ मन आशावादी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी और सुधारवादी होता है। इसके विपरीत पतनोन्मुख मन सदा निराश रहने वाला, तुरन्त की बात सोचने वाला, भाग्यवादी, कठिनाइयों की बात सोच-सोचकर खिन्न रहने वाला होता है। वह परिस्थितियों के निर्माण में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता। मन पत्थर या कांच का बना नहीं होता जो बदला न जा सके। प्रयत्न करने पर मन को सुधारा और बदला जा सकता है। समाज निर्माण का प्रमुख सुधार यह मानसिक परिवर्तन ही है। हमारा मन यदि अग्रगामी पथ पर बढ़ने की दिशा पकड़ ले, तो जीवन के सुख-शान्ति और भविष्य के उज्ज्वल बनने में कोई संदेह नहीं रह जाता। जिनने आशा और उत्साह का स्वभाव बना लिया है, वे उज्ज्वल भविष्य के उदीयमान सूर्य पर विश्वास करते हैं। ठीक है, कभी-कभी कोई बदली भी आ जाती है और धूप कुछ देर के लिए रु क भी जाती है। पर बादलों के कारण सूर्य सदा के लिए अस्त नहीं हो सकता है। असफलताएं और बाधाएं आते रहना स्वाभाविक है। कठिनाइयां मनुष्य के पुरुषार्थ को जगाने और आगे बढ़ने की चेतावनी देने आती हैं। आज यदि सफलता मिली है, प्रतिकूलता उपस्थित है, संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो कल उस स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आशावादी व्यक्ति छोटी-छोटी असफलताओं की परवाह नहीं करते। वे रास्ता खोजते हैं और धैर्य, साहस, विवेक एवं पुरुषार्थ को मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, क्योंकि आपत्ति के समय में यही चार सच्चे मित्र बताए गए हैं।

आज का राशिफल

मेष पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आपके वर्चस्व तथा प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।

वृषभ जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। रुके हुए कार्य सम्पन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे।

मिथुन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। आर्थिक लाभ होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।

कर्क पारिवारिक जनों के मध्य सुखद समाचार मिलेगा। रोजी रोजगार के प्रयास सफल होंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

सिंह व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाणी की सौम्यता से रुके हुए कार्य सम्पन्न होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे।

कन्या जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।

तुला पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है।

वृश्चिक आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। व्यावसायिक दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। विरोधियों का पराभव होगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

धनु पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मकर राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। आर्थिक संकट से गुजरना होगा। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलायेगी।

कुम्भ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। टकराव की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन आगमन होगा। कुटुम्बजनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

मीन कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। भारी व्यय का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात और भारत

- प्रभुनाथ शुक्ल

दुनिया में लगता है शांति संभव नहीं है। ग्लोबल स्तर पर युद्ध की अशांति फैली हुई है। बुद्ध का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है। शक्तिशाली स्थितियां निर्बल को कमजोर बना रही हैं। दुनिया की सारी शक्तियां कुछ देशों के साथ सिमट कर रह गई हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी संस्थाएं बेमतलब साबित हो रही हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अशांति फैली है। तालिबान की वजह से लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को बाध्य हैं। हजारों की संख्या में रोज पलायन हो रहा है। तालिबान निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रहा है। जिसमें सेना, शिक्षाविद, पत्रकार, साहित्यकार और दूसरे तमाम लोग शामिल है। हजारों निर्दोष जंग में शहीद हो चुके हैं। अफ्गानिस्तान जैसा संप्रभु मुल्क अशांत है। दुनिया शांत होकर इस युद्ध को देख रही है। फिलिस्तीन और इजरायल की तरह युद्ध में बेगुनाह और बेजुबान लोग मारे जा रहे हैं। मानवीय अधिकारों का खुला हनन हो रहा है। तालिबान दुनिया के शक्तिशाली देशों को चुनौती दे रहा है। जबकि तालिबानी जिहादियों को भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खाद-पानी दे रहा है। अफगानिस्तान में कब शांति लौटेगी अपने आप में यह बड़ा सवाल है। गुटों में विभाजित वैश्विक शक्तियां जानबूझकर इस खेल पर मौन हैं। अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थितियों को लेकर रूस ने चिंता जाहिर की है। शुभ संकेत मिले हैं कि इस मसले पर अमेरिका, चीन और रूस के साथ पाकिस्तान की एक बैठक कतर में होनी है। जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस बैठक में भारत को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि रूस की निगाह में तालिबान पर भारत का कोई असर नहीं है। इस बैठक में उन्हीं देशों को शामिल किया गया है जो दक्षिण एशिया के देशों पर अपना-अपना प्रभाव रखते हैं। हालांकि अफगानिस्तान के कई इलाकों पर तालिबानी लड़ाकों द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। समझौते में अगर कोई हल निकलता भी जाता है तो इसके बावजूद अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि तालिबान जितनी जमीन पर कब्जा जमा लेगा उसे वह छोड़ना नहीं चाहेगा। जिसकी वजह से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच संबंधों में हमेशा तनाव बना रहेगा। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों को खुलेआम मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। यह बात चीन, रूस और अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है। इसके बावजूद तीनों महाशक्तियों ने चुप्पी साध रखी है। क्योंकि वह चाहती हैं कि दक्षिण एशिया में अशांति का माहौल बना रहे। पाकिस्तान आतंक की नर्सरी तैयार करता रहे। कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद फलता-फूलता रहे। अफगानिस्तान में तालिबान अपना काम करता रहे। अगर दक्षिण एशिया में शांति रहेगी तो फिर महाशक्तियों को कौन पूछेगा। कैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन का सैन्य कारोबार चलेगा। उनकी पाण्डुब्बियाँ, युद्धपोत, रडार, युद्धक विमान और आणविक हथियार कौन खरीदेगा। अपनी दादागिरी कायम करने के लिए विश्व की शक्तियाँ शान्ति का कभी समर्थन नहीं करना चाहती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें जितनी मजबूत होगी, भारत के लिए उतना खतरा बढ़ेगा। अफगानिस्तान भारत का समर्थक रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए कई बिलियन डालर का निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता तालिबान को नहीं पचती। पाकिस्तान का आका चीन भी भारत के इस सहयोग से जलता है। क्योंकि पाकिस्तान में उसकी दाल गल जाती है लेकिन अफगानिस्तान में उसकी एक भी नहीं चलती। अफगानिस्तान अमेरिका और भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। जिसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबानियों को मिर्ची लगती है। तालिबान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। वह कट्टर इस्लामिक संस्कृति का समर्थक है। जबकि सभ्य इस्लामिक मुल्क इसकी इजाजत नहीं देते, जिसकी वजह से वह अलग-थलग पड़ जाता है। शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध की अनगिनत मूर्तियों को तालिबान ढहा चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान अगर मजबूत हो गया तो चीन पाकिस्तान की मदद से भारत को अस्थिर करने का जाल बुनेगा। क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन सिर्फ भारत से डरता है। हाल के दिनों में नेपाल से भी भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। वहां चीन की दखलअंदाजी बढ़ी है। जिसकी वजह से यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद राज्य के लश्कर गाह और कंधार के जिलों में तालिबानी और अफगानिस्तान के सैन्य बलों के बीच घमासान मचा है। यहां हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। वैश्विक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की विभीषिका के बीच हर रोज तकरीबन तीस हजार लोग अफगानिस्तान से पलायन कर रहे हैं। अधिकांश लोग शरणार्थी शिविरों में है। जबकि तालिबानियों का दावा है कि उन्होंने देश की कई सीमाओं को सील कर दिया है। तालिबान अस्पतालों के साथ और प्रमुख सरकारी संस्थानों को निशाना बना रहा है। तालिबान की वजह से 10 सालों में तकरीबन पचास लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 200 जिलों में तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान के आतंक से परेशान होकर दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस साल अब तकरीबन लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। वर्तमान हालात में सीमा पार करने वाले अफगानिस्तानियों की संख्या में 30 से 40 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफल हो गया तो आने वाले दिनों के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। अब वक्त आ गया है जब वैश्विक दुनिया को एक मंच पर आकर अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भारत, अफगानिस्तान में हमेशा शांति का प्रबल समर्थक रहा है। भारत पूरी दुनिया को एक परिवार समझता है। वह खुद और दूसरों के साथ सौहार्द चाहता है। भारत युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रुपये में दूसरे दिन भी गिरावट, 17 पैसे कमजोर होकर 74.43 रुपये प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई. रुपये में दूसरे कारोबारी सत्र में भी मंगलवार को गिरावट देखी गई। विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने के कारण अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ 74.43 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सुबह रुपया 74.40 पर खुला। कारोबार के दौरान रुपया 74.33 से 74.46 रुपये के दायरे में घट बढ़ के बाद पिछले सत्र के बंद भाव के मुकाबले 17 पैसे लुढ़क कर 74.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया सोमवार को 74.26 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। पिछले दो कारोबारी सत्रों में रुपये में 28 पैसे की गिरावट आई है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 93.04 हो गया। वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.98 प्रतिशत बढ़कर 69.72 डॉलर प्रति बैरल हो गया। वहीं, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 151.81 अंक बढ़कर 54,554.66 अंक पर बंद हुआ।

अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, 7 दिनों में निर्यात 50% बढ़कर 7.41 अरब डॉलर पर पहुंचा

नई दिल्ली: देश का निर्यात एक से सात अगस्त के दौरान 50.45 प्रतिशत बढ़कर 7.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषणों का निर्यात अच्छा रहने से कुल निर्यात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार एक से सात अगस्त के दौरान आयात भी 70 प्रतिशत बढ़कर 10.45 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह व्यापार घाटा तीन अरब डॉलर रहा। समीक्षाधीन अवधि में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 63 प्रतिशत बढ़कर 83.4 करोड़ डॉलर रहा। इसी तरह रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 121 प्रतिशत बढ़कर 41.8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 14.5 प्रतिशत बढ़कर 52.2 करोड़ डॉलर रहा। हालांकि, इस दौरान लौह अयस्त, खली तथा तिलहन के निर्यात में गिरावट आई। एक से सात अगस्त के दौरान देश का कच्चे तेल का आयात 141 प्रतिशत बढ़कर 1.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात 31 प्रतिशत बढ़कर 30.8 करोड़ डॉलर रहा। समीक्षाधीन अवधि में सोने का आयात 12.48 प्रतिशत घटकर 10 करोड़ डॉलर रह गया। इस दौरान अमेरिका को निर्यात 48.4 प्रतिशत बढ़कर 46.27 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात 70 प्रतिशत बढ़कर 20.97 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब को 180 प्रतिशत बढ़कर 16.4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।

शेयर बाजार रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुआ

सेंसेक्स 54,554 , निफ्टी 16,280 पर बंद

मुंबई।

मुम्बई शेयर बाजार मंगलवार को रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही एचडीएफसी, भारती एयरटेल और इन्फोसिस के शेयरों में बढ़त से बाजार मजबूत हुआ है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 151.81 अंक करीब 0.28 फीसदी की बढ़त के साथ ही रिकार्ड 54,554.66 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21.85 अंक तकरीबन 0.13 फीसदी की तेजी के साथ 16,280.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा करीब चार फीसदी की तेजी भारती एयरटेल में रही। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक में भी उछाला आया। वहीं दूसरी ओर, टाटा स्टील, एनटीपीसी, आईटीसी और पावर ग्रिड में गिरावट रही। जानकारों के अनुसार यह मुख्य रूप से धातु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और रियल्टी शेयरों में बिकवाली के दबाव से आयी।'' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य वित्तीय शेयरों से बाजार को समर्थन मिला और बड़ी गिरावट पर अंकुश लगा रहा। बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों ने आईटी कंपनियों के शेयरों को वरीयता दी। इससे पहले सुबह बाजार तेजी के साथ खुला। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में उछाल से बाजार ऊपर आया। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 257.31 अंक करीब 0.47 फीसदी की बढ़त के साथ ही 54,660.16 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 64.05 अंक की बढ़त के साथ ही 16,322.30 अंक पर था।

राजस्व घाटा पूरा करने के लिए 17 राज्यों को 9871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की भरपाई करने के लिए नौ अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की थी कि 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिया जाये। यह अनुदान प्राप्त करने के लिये कौन से राज्य पात्र हैं, इसका फैसला वित्त आयोग करता है। वह राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिये मूल्यांकन किया गया। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपये (41.67 प्रतिशत) की रकम जारी की गई है। 15वें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

अगले 1 साल में 73 प्रतिशत भारतीय कंपनियों को ग्राहक डेटा उल्लंघन का खतरा

बेंगलुरु।

भारत में लगभग 73 प्रतिशत संगठनों या कंपनियों को अगले 12 महीनों में डेटा उल्लंघन का अनुभव होने की उम्मीद है, जो अगले 12 महीनों में ग्राहकों के डेटा को प्रभावित करेगा। एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को यह अंदेशा जताया गया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा लीडर ट्रेंड माइक्रो के अनुसार, भारतीय संगठनों ने एक हमले के शीर्ष तीन नकारात्मक परिणामों को खोए हुए आईपी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति/व्यवधान और बाहरी सलाहकारों एवं विशेषज्ञों के नुकसान के रूप में स्थान दिया है। ट्रेंड माइक्रो के कंट्री मैनेजर (इंडिया एंड सार्क), विजेंद्र कटियार ने कहा, एक बार फिर, हमने परिचालन और बुनियादी ढांचे के जोखिम से लेकर डेटा सुरक्षा, खतरे की गतिविधि और मानव-आकार की चुनौतियों तक सीआईएसओ को रात में जगाए रखने के लिए बहुत कुछ पाया है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग 57 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने कहा है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगले 12 महीनों में उन पर गंभीर साइबर हमले होंगे। जबकि नेटवर्क/सिस्टम में घुसपैठ से संबंधित

34 प्रतिशत को 7 से अधिक साइबर हमलों का सामना किए जाने की बात कही गई है, वहीं 20 प्रतिशत ने संपत्ति के 7 से अधिक उल्लंघनों का सामना किए जाने की पुष्टि हुई है। उत्तरदाताओं में से 30 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें पिछले एक साल में ग्राहक डेटा के 7 से अधिक उल्लंघनों का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हाइलाइट किए गए शीर्ष साइबर खतरों में रैंसमवेयर, वाटरिंग होल अटैक, बॉटनेट, दुर्भावनापूर्ण अंदरूनी सूत्र और उन्नत लगातार खतरे (एपीटी) शामिल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के लिए शीर्ष सुरक्षा जोखिमों में दुर्भावनापूर्ण अंदरूनी सूत्र, क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना और प्रदाता, संगठनात्मक मिसलिग्नमेंट और जटिलता के साथ-साथ लापरवाह अंदरूनी सूत्र शामिल हैं। कटियार ने कहा, साइबर जोखिम को कम करने के लिए, संगठनों को बुनियादी बातों पर वापस जाकर, सबसे अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण डेटा की पहचान करके, उन खतरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उनके व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और व्यापक रूप से जुड़े प्लेटफार्मों से बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इंडिया इंक ने जुलाई में 13.2 अरब डॉलर के 181 सौदे किए

नई दिल्ली।

ग्रांट थॉर्नटन भारत के डीलट्रैकर के अनुसार, भारत इंक ने जुलाई 2021 में 13.2 अरब डॉलर के 181 सौदे दर्ज किए। डील वॉल्यूम में साल-दर-साल 66 फीसदी और डील वैल्यू में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह साल 2005 के बाद से किसी भी महीने के लिए उच्चतम रिकॉर्ड वॉल्यूम भी है। ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर शांति विजेथा, ने कहा, सौदा गतिविधि में यह उछाल मुख्य रूप से कंपनियों द्वारा आर्थिक रूप से उधार लेना जारी रखने और परिवर्तनकारी सौदों पर अपने नकदी भंडार को खर्च करने के बाद कोविड -19 दुनिया के लिए खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए था। कॉर्पोरेट भारत ने पहले संकट की स्थिति में चपलता और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया है। विजेथा ने कहा, सरकारी सुधार और जनसांख्यिकीय लाभ प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता को और दोहराते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में भी सौदे की प्रवृत्ति पॉजिटिव बनी रहेगी। विलय और अधिग्रहण में सौदे की गतिविधि में जुलाई 2021 में 5.6 बिलियन डॉलर के 36 सौदे हुए। जुलाई 2020 की तुलना में वॉल्यूम में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सौदे के मूल्यों में 37 प्रतिशत की गिरावट आई। यह मुख्य रूप से बड़े-टिकट लेनदेन में कमी के कारण था। पीई/वीसी निवेश खंड में 7.5 अरब डॉलर मूल्य के 145 सौदे हुए। रिकॉर्ड उच्च सौदों को इक्विटी में उछाल, उच्च तरलता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ी हुई रुचि से तेज किया गया है। देश भर के व्यवसाय रिबाउंड प्रक्षेपवक्र पर हैं जिसके परिणामस्वरूप उधार देने में सुधार हुआ है जिससे उच्च पीई सौदों को रिकॉर्ड किया गया है। 2019-20 की तुलना में उनके मूल्यांकन में भारी वृद्धि के साथ महामारी द्वारा ऑनलाइन व्यापार मॉडल को बहुत तेज किया गया है। जुलाई 2021 में वॉल्यूम चार्ट में एमएंडए और पीई दोनों सेगमेंट में स्टार्ट-अप ने 109 सौदों के साथ 1.6 बिलियन डॉलर की राशि हासिल की। इस महीने में कई स्टार्ट-अप ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ सार्वजनिक होने की अपनी योजनाओं की घोषणा की। जोमैटो, पेटीएम, नायका और ओला कुछ सबसे बड़े नाम हैं जिन्होंने आईपीओ के लिए उनकी योजनाओं का संकेत दिया। जोमेटो के पास एक ब्लॉकबस्टर कार्यकाल था क्योंकि उसे आईपीओ के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपये के करीब आवेदन प्राप्त हुए थे। बायजू द्वारा एड-टेक कंपनी यूएसए की एपिक का 500 मिलियन डॉलर में

अधिग्रहण, जिसके बाद ग्रेट लर्निंग ने 600 मिलियन डॉलर और फ्लिपकार्ट ने वैश्विक निवेशकों से नए फंड में 3.6 डॉलर बिलियन जुटाए, जो महीने का मुख्य आकर्षण रहा है। इस साल अब तक अरब डॉलर के 10 सौदे और 100 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 81 सौदे हुए हैं। इन उच्च मूल्य के सौदों ने 2021 में कुल सौदे मूल्यों का 84 प्रतिशत हिस्सा लिया। 2021 में सौदे के मूल्यों में वृद्धि का समर्थन करते हुए, 2020 में सात की तुलना में 2021 में 13 यूनीकार्न रहे हैं।

सोना 176 रुपये, चांदी 898 रुपये लुढ़की

नयी दिल्ली.

दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 176 रुपये की गिरावट के साथ 45,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। सोने का पिछला बंद भाव 45,286 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत भी 898 रुपये लुढ़ककर 61,715 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इसका पिछला बंद भाव 62,663 रुपये प्रति किलो पर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,735 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 23.56 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल के अनुसार, ''डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमत हाल के निम्न स्तर से उठी तो है लेकिन अब भी यह पांच माह के निम्न स्तर के आसपास चल रही है।''

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में जून तिमाही में बिक्री 34 मिलियन यूनिट तक पहुंची : आईडीसी

नई दिल्ली।

भारत के स्मार्टफोन बाजार ने अप्रैल-जून तिमाही में दूसरी लहर के बीच कम नोट पर शुरूआत की, लेकिन अंत में जल्दी से सुधार आया और इसकी बिक्री 86 प्रतिशत साल-दर-साल की वृद्धि 34 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। मंगलवार को आईडीसी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। ऑनलाइन चैनल के त्वरित विकास के परिणामस्वरूप 113 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ 51 प्रतिशत की रिकॉर्ड हिस्सेदारी हुई है। दूसरी तरफ, आईडीसी के त्रैमासिक मोबाइल फोन ट्रैकर के अनुसार, मई और मध्य जून के दौरान कई क्षेत्रों में सप्ताहांत के कर्फ्यू और आंशिक रूप से खुले बाजारों (ऑड ओब्लिक ईवन योजनाओं के साथ) से ऑफलाइन चैनल प्रभावित हुआ है। आईडीसी इंडिया के अनुसंधान निदेशक (क्लाइंट डिवाइसेस एंड आईपीडीएस) नवकेंद्र सिंह ने कहा,जबकि 2021 में एकल अंकों की वृद्धि देखने की उम्मीद है, 2एच21 में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में गिरावट की संभावना है।

कम मांग के साथ, तीसरी लहर के आसपास अनिश्चितता, लगातार आपूर्ति की कमी, और बढ़ती मुद्रास्फीति दरों के साथ-साथ बढ़ती घटती रहती हैं। सिंह ने कहा,फिर भी 2022 में एक रिबाउंड कम-मध्य मूल्य खंडों में अपग्रेडर्स के साथ संभव होगा। 5जी डिवाइस की आपूर्ति-आधारित, आने वाले महीनों में अपेक्षित नई पेशकशों के साथ फीचर फोन माइग्रेशन (रिलायंस जियो द्वारा घोषित) और बेहतर आपूर्ति के साथ बाजार रहेगा। मीडियाटेक-आधारित स्मार्टफोन ने उप 200 डॉलर सेगमेंट में 64 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ नेतृत्व करना जारी रखा, जबकि क्वालकॉम यूएस 200-500 डॉलर सेगमेंट में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ हावी रहा है। शाओमी ने 84 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ नेतृत्व किया। शाओमी ने ऑनलाइन चैनलों में अपने शिपमेंट के लगभग 70 प्रतिशत के साथ 40 प्रतिशत ऑनलाइन बाजार हिस्सेदारी किया है।

सैमसंग दूसरे स्थान पर था, शीर्ष 10 विक्रेताओं में सबसे कम सालाना वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 15 प्रतिशत दर्ज की गई। वीवो 57 फीसदी सालाना ग्रोथ के साथ तीसरे स्थान पर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियलमी ने 175 फीसदी सालाना की शिपमेंट ग्रोथ के साथ चौथे स्थान के लिए ओप्पो को पीछे छोड़ दिया है।

वेस्टीज को मिला कमिटमेंट टू बीइंग ए ग्रेट प्लेस टू वर्क का सम्मान

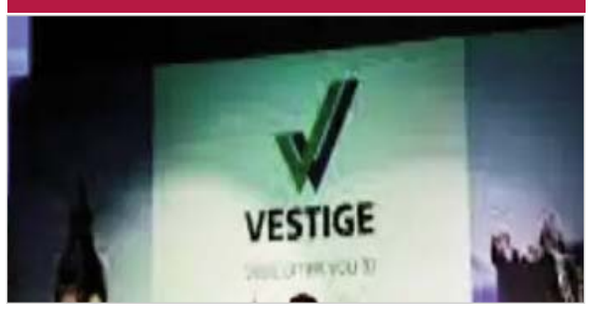

नई दिल्ली।

हाई-ट्रस्ट, हाई-परफॉर्मेंस कल्चर के 5 आयामों-विश्वसनीयता, सम्मान, निष्पक्षता, गौरव और सौहार्द पर उत्कृष्टता के लिए वेस्टीज मार्केटिंग लिमिटेड की निरंतर प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए, भारत की एकमात्र प्रमुख घरेलू प्रत्यक्ष बिक्री है। कंपनी, को लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का सम्मान किया गया है। वेस्टीज मार्केटिंग लिमिटेड ने लगातार तीन बार काम करने के लिए शानदार जगह हासिल की है, 2019 और 2020 में एक मध्यम आकार का कार्यस्थल है। यह 2021 में ग्रेट लार्ज-साइज वर्कप्लेस की श्रेणी में प्रवेश किया है। जो इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यह सम्मान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा दिया गया है। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री गौतम बाली ने प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण जीतने पर वेस्टीज पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, हम काम करने के लिए एक महान जगह होने के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता प्राप्त करने के लिए रोमांचित हैं। यह सम्मान हमारे निरंतर प्रयास को मान्यता देता है। हमारा कार्यस्थल सकारात्मक उत्पादकता का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारे कार्यालयों, वितरण बिंदुओं और हमारे लाखों वितरकों के दिलों में सामंजस्य, प्रशंसा और विश्वास की संस्कृति बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों ने हमें इस उपलब्धि की ओर अग्रसर किया है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान ने उन संगठनों का अध्ययन किया है।

जिन्होंने फीडबैक के आधार पर बेहतर कर्मचारी अनुभव प्रदान करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। ये संगठन एक महान कार्यस्थल अनुभव के निर्माण की दिशा में अपने इरादे के प्रतिबद्ध हैं। उनके प्रयासों को कर्मचारियों द्वारा साल-दर-साल समर्थन दिया गया है।

43.7 प्रतिशत आईफोन यूजर्स आईफोन 13 में अपग्रेड फीचर होने की उम्मीद - रिपोर्ट

सैन फ्रांसिस्को।

एप्पल नए आईफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में एक नए सर्वेक्षण से पता चला है कि मौजूदा आईफोन यूजर्स में से करीब 44 फीसदी आईफोन 13 मॉडल में अपग्रेड फीचर चाहते हैं। सेलसेल के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, 43.7 प्रतिशत आईफोन उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे आईफोन 13 पर स्विच करने की योजना बना रहे हैं, जो पिछले साल एक सर्वेक्षण से आईफोन 12 खरीद के इरादे की तुलना में 2.7 प्रतिशत अधिक है। जबकि 56.3 प्रतिशत ने खुलासा किया कि वे आगामी आईफोन रेंज में रुचि नहीं रखते हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उच्च रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, अंडर-डिस्प्ले टच आईडी, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और छोटे नॉच, नॉच-लेस डिजाइन आईफोन 13 की सबसे रोमांचक अफवाह वाली विशेषताओं की सूची में 22 प्रतिशत, 18.2 प्रतिशत, 16 प्रतिशत पर सबसे ऊपर हैं, क्रमश 10.9 प्रतिशत है। पहले आईफोन 12 की तरह, आईफोन 13 भी चार वेरिएंट में उपलब्ध होगा 5.4 इंच आईफोन 13 मिनि, 6.1-इंच आईफोन 13, 6.1-इंच आईफोन 13 प्रो और 6.7-इंच आईफोन 13 प्रो मेक्स, अफवाहों के बावजूद उस पर खराब बिक्री के कारण एप्पल मिनी मॉडल को छोड़ सकता है। मानक आईफोन 13 38डॉट2 प्रतिशत पर सबसे लोकप्रिय पिक था, इसके बाद आईफोन 13 प्रो मैक्स 30.8 प्रतिशत था। 24 प्रतिशत ने कहा कि वे आईफोन 13 प्रो मॉडल के लिए जाएंगे, जबकि केवल 7 प्रतिशत छोटे आईफोन 13 मिनी में रुचि रखते हैं। वियरेबल्स में से, 27.3 प्रतिशत आईफोन मालिकों ने कहा कि वे एप्पल वॉच सीरीज 7 को खरीदने पर विचार करेंगे क्योंकि यह इस साल के अंत में रिलीज होगी। दूसरी ओर, केवल 12.9 प्रतिशत ने एप्पल एयारपोडस के तीसरे संस्करण को खरीदने में रुचि व्यक्त की, एक नए डिजाइन, शोर रद्द करने की सुविधा, स्थानिक ऑडियो समर्थन और बहुत कुछ के बारे में अफवाहों के बावजूद। ऑनलाइन सर्वेक्षण 28 जुलाई से 6 अगस्त, 2021 के बीच आयोजित किया गया। जिसमें अमेरिका में स्थित 3,000 से अधिक आईफोन यूजर्स शामिल थे, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थे।

पिछले 5 सालों में एनसीआर में औसत टिकट की कीमत, संपत्ति का आकार घटा

नई दिल्ली।

पिछले कुछ सालों में नियामक परिवर्तनों और किफायती आवास की व्यापक स्वीकृति के साथ संपत्ति बाजार में काफी विकास हुआ है, इसलिए औसत टिकट मूल्य और मांग में संपत्तियों के आकार में 2016-2021 के दौरान गिरावट आई है। एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लॉन्च की जा रही संपत्तियों की औसत टिकट कीमत 68.20 लाख रुपये (2010-2015 के दौरान) से घटकर 56.25 लाख रुपये (2016 से एच1 2021) हो गई है। किफायती और मध्यम वर्ग के घरों की बढ़ती मांग ने इस बदलाव का नेतृत्व किया है। इसके अलावा, घरों का औसत आकार भी 2010-2015 में 1,550 वर्ग फुट से घटकर 2016 से 2021 की पहली छमाही के बीच 1,250 प्रति वर्ग फुट हो गया है। उन्होंने कहा, जबकि डेवलपर्स ने कीमतों को कम करने के लिए घर के आकार को कम कर दिया और उन्हें अब इस पहलू पर पुनर्विचार करना होगा कि महामारी द्वारा लाई गई डब्ल्यूएफएच और ई-स्कूलिंग वास्तविकताओं को समायोजित करने के लिए बड़े स्थानों की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, एनसीआर में रियल्टी बाजार में चलन पर, एनरॉक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 और 2015 के बीच स्थानीय खिलाड़ियों के गौरवशाली दिनों से, 2016 और एच 1 2021 के बीच की अवधि में एनसीआर हाउसिंग मार्केट पूरी तरह से बदल गया है। एक बाजार जो कभी सट्टेबाजों द्वारा संचालित होने के लिए कुख्यात था, एनसीआर बेईमान डेवलपर्स के

लिए अनियंत्रित और अनावश्यक सूची को मंथन करने, सट्टेबाजों की गैलरी में पूरी तरह से खेलने, अनजाने घर खरीदारों के विश्वास को भुनाने और उनके पैसे को कहीं और मोड़ने के लिए एक वास्तविक शिकार का मैदान था। एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं, इस अवधि के परिणाम अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बीसीसीआई ने एनसीए के शीर्ष पद के लिए आवेदन मंगाए

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के शीर्ष पद के लिए आवेदन मंगाए हैं जिस पद पर फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ हैं।अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने लिखा कि वह एनसीए में हेड ऑफ क्रिकेट पद के लिए आवेदन मांग रहा है। द्रविड़ भी इस पद के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं और इसका कार्यकाल दो साल का होगा। बोर्ड ने विज्ञापन में कहा, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, बैंगलोर में सभी क्रिकेट कोचिंग कार्यक्रमों को चलाने के लिए हेड क्रिकेट एनसीए समग्र रूप से जिम्मेदार होगा। वह अकादमी में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी क्रिकेटरों की तैयारी, विकास और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। द्रविड़ को जुलाई 2019 में एनसीए में हेड ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया गया था और इस दौरान कई युवाओं ने बेहतर प्रगति करते हुए इंडियन टीम में जगह बनाई। द्रविड़ को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया था। मौजूदा भारतीय कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप के बाद खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल आगे बढेगा या नहीं यह टीम के इंग्लैंड में और टी20 विश्व कप में प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

भारतीय महिला टीम का सितंबर में होगा ऑस्ट्रेलियाई दौरा

रहना होगा क्वारंटीन में

नई दिल्ली ।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने सितंबर-अक्तूबर में होने वाले आस्ट्रेलिया दौर से पहले ट्रेनिंग शिविर के लिए बेंगलुरू में एकत्रित होना शुरू कर दिया है। इस पूर्ण दौरे के लिए टीमों की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन लगभग 30 क्रिकेटरों को मंगलवार शाम तक बेंगलुरू पहुंचने को कहा गया है। खिलाड़ी छह दिन के पृथकवास के बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगी। अभी इंग्लैंड में द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेल रही हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा को 22 अगस्त तक बेंगलुरू में राष्ट्रीय टीम से जुड़ने को कहा गया है क्योंकि इस महीने के अंत में टीम के आस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले इन्हें भी छह दिन के पृथकवास से गुजरना होगा। हंड्रेड टूर्नामेंट 21 अगस्त तक चलेगा। आस्ट्रेलिया पहुंचने पर खिलाड़ियों को 14 दिन के पृथकवास से गुजरना होगा जिसके बाद सिडनी में मेजबान आस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इस दौरे पर भारत तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय, एक दिन-रात्रि टेस्ट और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि आस्ट्रेलिया में पहले हफ्ते कड़े पृथकवास से गुजरना होगा।

इसके बाद टीम को अगले सात दिन ट्रेनिंग की स्वीकृति मिलने की संभावना है जिसके साथ उनका पृथकवास पूरा होगा। इंग्लैंड दौरे के बाद यह भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण दौरा होगा। भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप की तैयारी कर रही है। भारतीय टीम के लिए पर्थ के वाका में गुलाबी गेंद का टेस्ट दौरे की सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि महिला टीम घरेलू क्रिकेट में भी लाल गेंद से नहीं खेलती है। भारत ने हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराया था जो लगभग सात साल में टीम का पहला टेस्ट था। भारत को एक दिवसीय और टी20 श्रृंखला दोनों में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की सदस्य शांता रंगास्वामी ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आस्ट्रेलिया के लिए खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले गुलाबी गेंद से घरेलू प्रतियोगिता का आयोजन कराने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

एएफआईराष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगा 7 अगस्त का दिन

नई दिल्ली :

नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगा। इस 23 वर्षीय एथलीट ने शनिवार को 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। चोपड़ा सहित अन्य एथलीटों के सम्मान समारोह के दौरान एएफआई के योजना आयोग के चेयरमैन ललित भनोट ने कहा, 'पूरे भारत में भाला फेंक को बढ़ावा देने के लिए हम सात अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे और अगले साल से हमारी मान्यता प्राप्त इकाइयां इस दिन अपने अपने राज्यों में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगी। उन्होंने कहा, 'इसके बाद अंतर जिला प्रतियोगिताएं होंगी और हम भाला मुहैया कराएंगे (क्योंकि काफी भालों की जरूरत होगी)। आगामी वर्षों में हम इस प्रतियोगिता में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता बनाएंगे। एएफआई ने 2018 में राष्ट्रीय ओपन भाला फेंक चैंपियनशिप शुरू की थी जिसका तीसरा टूर्नामेंट इस साल अक्तूबर में होगा। चोपड़ा ने कहा, 'मुझे खुशी है कि एएफआई आगामी दिनों में मेरी उपलब्धि को याद रखने पर काम कर रहा है। अगर मेरी उपलब्धि इस देश के युवाओं के एथलेटिक्स, विशेषकर भाला फेंक से जुड़ने का कारण बनती है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा, 'बच्चों को अगर भाला और अन्य सुविधाएं मिलती हैं तो मुझे उम्मीद है कि वे इस खेल से जुड़ेंगे और मुझे उनकी हौसलाअफजाई करने में खुशी होगी। वे भविष्य के पदक विजेता हो सकते हैं।

रीगा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल शतरंज - दूसरे वरीय निहाल नें जीत से की शुरुआत

रीगा , लातविया (निकलेश जैन) कोविड के प्रभाव के बावजूद अब धीरे धीरे शतरंज की दुनिया मे टूर्नामेंट की वापसी हो रही है । इसी क्रम मे दुनिया के 29 देशो के 176 खिलाड़ियों के बीच रीगा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट की कल शुरुआत हो गयी । भारत के 17 वर्षीय युवा ग्रांड मास्टर निहाल सरीन को प्रतियोगिता मे दूसरी वरीयता दी गयी है । अभी पिछले सप्ताह ही विश्व शतरंज संघ द्वारा जारी की गयी फीडे रेटिंग मे निहाल लंबी छलांग लगाते हुए 2655 एलो अंको के साथ दुनिया के शीर्ष 100 मे 88 वे स्थान पर पहुँच गए है और 17 वर्ष मे किसी भी भारतीय द्वारा हासिल की गयी अब तक की यह सर्वाधिक रेटिंग है । पहले राउंड मे निहाल नें आयरलैंड की तृशा कन्यामराला को पराजित करते हुए अच्छी शुरुआत की है । हालांकि प्रतियोगिता मे खेल रहे चौंथे वरीय ग्रांड मास्टर एसपी सेथुरमन को मेजबान लातविया के 91 वे वरीय सालना अलेक्सांद्रास नें पराजित कर बड़ा उलटफेर कर दिया । अन्य भारतीय ग्रांड मास्टर अरविंद चितांबरम , एसएल नारायनन , अभिमन्यु पौराणिक , विकाश एनआर ,अर्जुन कल्याण और राजा हर्षित नें जीत के साथ शुरुआत की है जबकि मुरली कार्तिकेयन ,आर प्रग्गानंधा और गुकेश को पहले दिन अपने से कम वरीय खिलाड़ियों से आधा अंक बांटना पड़ा है ।

नीरज चोपड़ा ने बताया- आखिर मिल्खा सिंह को ही क्यों समर्पित किया स्वर्ण पदक

नई दिल्ली ।

टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह खेल में अपना अभ्यास जारी रखेंगे और अपने ऊपर सुपर स्टार वाली सोच (सफलता का खुमार) कभी हावी नहीं होने देंगे। चोपड़ा ने चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि एक खिलाड़ी के लिए ऐसी मानसिकता होना खतरनाक है और उनका पूरा ध्यान खेल पर ही रहेगा। चोपड़ा से जब पूछा गया कि इस वक्त आपके प्रशंसकों की संख्या (फैन फॉलोइंग) किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है, खासकर लड़कियों में, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा ध्यान खेल पर रखना चाहता हूं, मैं अपना पूरा ध्यान खेल पर रखना चाहता हूं। मैं इस बारे में तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है कि उनकी तरफ से इतना प्यार मिल रहा है लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान अगले साल होने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के अलावा आने वाले टूर्नामेंट और (अगले) ओलंपिक पर है। चोपड़ा ने सोमवार को टोक्यो में भाला फेंक के फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। यह भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहला पदक है। वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि वह उसी समय देखेंगे, उसके बारे में उसी समय पता चलेगा लेकिन मैं अपनी तरफ से उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, और इस चीज से थोड़ी कोशिश करूंगा। जैसा आपने कहा कि सुपरस्टार वाली सोच वो थोड़ा न ही आए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने खेलों में ऐसी सोच को खतरनाक करार देते हुए कहा कि बस अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करुंगा और उसी पर ज्यादा ध्यान रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है वही चीज बहुत जरूरी है। खेलों में ऐसी सोच आना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। मैं खेल पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगा। अपने स्वर्ण पदक को मिल्खा सिंह के नाम किए जाने के बारे में पूछे जाने पर इस 23 साल के खिलाड़ी ने कहा कि मैंने उनका वह साक्षात्कार देखा था जिसमें वह कह रहे थे कि उनका एक सपना है कि कोई अपने देश का नौजवान या कोई भी लड़की वहां जाए और (एथलेटिक्स में) पदक लेकर आए और जब ऐसा हुआ तो खासकर राष्ट्रगान पर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती कि उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि जब भी चंडीगढ़ या पटियाला की तरफ जाता था तो मैं मिल्खा सिंह जी से मिलने के बारे में सोचता था।

संक्षिप्त समाचार

बार्सीलोना छोड़ने के बाद इस क्लब से जुड़ेंगे मेस्सी, मिलेंगे इतने अरब रूपए

पेरिस । लियोनेल मेस्सी पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद फ्रांस जाएंगे। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। इस करार से पहले बार्सीलोना के साथ अब तक का अपना पूरा करियर बिताने के बाद दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक मेस्सी के लिए नए क्लब के प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि अर्जेंटीना के इस 34 साल के दिग्गज ने पीएसजी के साथ दो साल का करार किया है जिसे आगे बढ़ाने का विकल्प है। यह जानकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर और आधिकारिक घोषणा से पहले चर्चा के अनुसार है। सूत्र ने बताया कि मेस्सी को सालाना लगभग 35 मिलियन यूरो (लगभग तीन अरब रुपये) मिलेगा। बार्सीलोना का अनुबंध समाप्त होने के बाद मेस्सी फुटबॉल इतिहास में किसी क्लब के लिए उपलब्ध होने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन गये हैं। पीएसजी के कोच मौरिसियो पोचेटिनो बार्सीलोना से अलग होने के बाद मेस्सी के संपर्क में थे।

ट्विटर पर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे चर्चित एथलीट रहे नीरज

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे चर्चित और भारत में हॉकी की टीम ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। 2016 रियो ओलंपिक की तुलना में इसमें 134 फीसदी का उछाल देखने को मिला। नीरज की सफलता के बाद ओलंपिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जश्न मनाने के वीडियो को भारत में सर्वाधिक बार देखा गया। 23 वर्षीय चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के बाद देश के लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने वाला ट्वीट भी भारत में ओलंपिक वार्तालापों में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला और री-ट्वीट किया गया ट्वीट था। भारत में ट्विटर पर हॉकी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई। हॉकी के अलावा अन्य जिन खेलों की चर्चा में वृद्धि दर्ज की गई उनमें भाला फेंक (प्लस 5631 प्रतिशत) और गोल्फ (प्लस 703 प्रतिशत) हैं। गोल्फ में अदिति अशोक पहली भारतीय महिला गोल्फर थीं जिन्होंने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। तलवारी में भवानी देवी के कारण 1086 प्रतिशत की बढोत्तरी दर्ज की गई। नीरज जहां भारत में सबसे ज्यादा चर्चित एथलीट रहे तो वहीं मीराबाई चानू दूसरे, पीवी सिंधु तीसरे, लवलीना बोरगोहेन चौथे, बजरंग पुनिया पांचवें और रानी रामपाल छठी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खिलाड़ी रहीं।

जोकोविच सिनसिनाटी ओपन से हटे, सीधे यूएस ओपन में खेलेंगे

सिनसिनाटी ।

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट (वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन) से हट गये हैं जिसका मतलब है कि अब वह यूएस ओपन के दौरान ही कोर्ट पर दिखेंगे जहां वह करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जोकोविच ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें आस्ट्रेलिया से लेकर तोक्यो तक के व्यस्त कार्यक्रम के बाद तरोताजा होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। इस साल ग्रैंडस्लैम में जोकोविच का रिकार्ड 21-0 है। उन्होंने फरवरी में हार्ड कोर्ट पर आस्ट्रेलियाई ओपन, जून में क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन और जुलाई में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन का खिताब जीता था। रॉड लीवर के 1969 में एक साल में चारों ग्रैंडस्लैम जीतने के बाद कोई भी पुरुष खिलाड़ी एक वर्ष में पहले तीन ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट नहीं जीत पाया था और जोकोविच के पास तो अब लीवर के रिकार्ड की बराबरी करने का मौका है।

विंबलडन के बाद जोकोविच ने एक सत्र में चारों ग्रैंडस्लैम और ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लक्ष्य के साथ तोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था लेकिन वह सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्सांद्र जेवरेव और कांस्य पदक के मुकाबले में स्पेन के पाब्लो कारेनो बस्टा से हार गये थे और इस तरह से पदक जीतने में असफल रहे थे।

ध्यान लगाने से मैचों के दौरान मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिली : सिंधु

हैदराबाद । ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि ध्यान लगाने से उन्हें अपने करियर में सफलताएं हासिल करने में मदद मिली क्योंकि इससे चित शांत रहता है और भावनाओं को बेहतर समझा जा सकता है। सिंधू ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'ध्यान लगाने से मैं शांतचित बनी रहती हूं और इससे मुझे भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। इससे मुझे अपनी आगे की योजनाओं को तैयार करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने यहां हर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का दौरा करने के बाद कहा, 'महामारी के इस तनावपूर्ण दौर में ध्यान से शांतचित बने रहने में मदद मिलती है। ध्यान लगाने से मुझे मेरे करियर में मदद मिली। मैं मैचों के दौरान मुश्किल परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकती हूं। सिंधू ने टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था। वह ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है।

अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रेन्स

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स को गंभीर हालत में ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार 51 साल के क्रेन्स की मुख्य धमनी की अंदरूनी परत फट गई थी जिसके बाद से ही उन्हें अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। केर्न्स की कई सर्जरी हुई है पर इसके बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। इस पूर्व क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगे थे, पर बाद में वह बरी हो गये थे। इसके बाद से ही उनकी आर्थिक हालत भी खराब हो गयी थी। यहां तक कि उन्हें बस धोने तक का काम करना पड़ा था। इस ऑलराउंडर ने अपने करियर में 62 टेस्ट और 215 एकदिवसीय खेले हैं। उन्हें 2000 में विज्डन ने साल के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक चुना था। उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में गिना जाता था। वो 2004 में बतौर ऑलराउंडर 200 विकेट और 3 हजार रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी बने थे। साल 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले केर्न्स ने न्यूजीलैंड के लिए 62 टेस्ट में 3320 रन बनाए जबकि 215 एकदिवसीय मुकाबलों में उनके नाम 4950 रन दर्ज हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 9 शतक और 48 अर्धशतक भी लगाए थे।

प्रधानमंत्री की उत्साहवर्धक बातों ने कांस्य पदक मुकाबले से पहले सकारात्मक ऊर्जा दी: मनप्रीत

नयी दिल्ली,

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि ओलंपिक सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्साहवर्धक बातों का अद्भुत असर हुआ जिसने खिलाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा की और टीम 41 साल बाद इन खेलों में पदक जीतने में सफल रही। विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बेल्जियम से 2-5 से हारने के बाद मोदी ने मनप्रीत और मुख्य कोच ग्राहम रीड से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी, जिससे पूरी टीम प्रेरित हुई। मनप्रीत ने कहा कि प्रोत्साहन के उन शब्दों ने अद्भुत तरीके से काम किया। भारतीय कप्तान ने कहा, '' सेमीफाइनल हारने के बाद हम सभी बहुत निराश थे, तभी कोच ने आकर कहा कि प्रधानमंत्री आप लोगों से बात करना चाहते हैं और जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा, 'आप सभी ने अच्छा खेला और निराश न हों, बस अपने खेल और अगले मैच पर ध्यान दें, देश को आप सभी पर गर्व है'।'' मनप्रीत ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिली और फिर हमने खिलाड़ियों की बैठक की। हमने कहा कि हमें एक और मौका मिला है और अगर हम खाली हाथ लौटते हैं तो हमें जीवन भर यही पछतावा रहेगा।'' उन्होंने कहा, '' हमने अपने आप से कहा कि हमारे हाथ में 60 मिनट हैं और अगर हम इन 60 मिनटों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो हम अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देश लौट सकते हैं।''भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 41 साल के अंतराल के बाद हाल ही कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने ओलंपिक में आठ स्वर्ण पदक जीते हैं। उसने आखिरी पदक 1980 के मास्को खेलों (स्वर्ण) में जीता था। मनप्रीत ने कहा, '' बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरा तीसरा ओलंपिक था और इस बार मैं टीम का कप्तान था। मेरा पहला ओलंपिक 2012 में काफी निराशाजनक रहा था क्योंकि हमने कोई मैच नहीं जीता था। लेकिन फिर हमने सुधार किया और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते। हमने 2016 में अच्छा खेला लेकिन क्वार्टर फाइनल की बाधा को पार नहीं कर सके।''

मनप्रीत ने कहा, '' इस बार हमारी मानसिकता अलग थी क्योंकि हमने काफी मेहनत की थी। हमने बेंगलुरु में एक साथ समय बिताया था। परिसर के अंदर पृथकवास पर थे। हम सभी दूसरों से अलग थे।

दिल्ली सरकार ने हमें ओलंपिक की तैयारी के लिए कभी आर्थिक मदद नहीं दी: एथलीट

नई दिल्ली।

दिल्ली सरकार ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के पांच एथलीटों के बैनर लगाकर अपना काम तो कर दिया है लेकिन एथलीटों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने हमें ओलंपिक की तैयारी के लिए कभी आर्थिक मदद नहीं दी। टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, शूटर दीपक कुमार और दो 400 मीटर धावक, अमोज जैकब और सार्थक भांबरी के बड़े-बड़े बैनर पूरे दिल्ली में लगाए गए हैं लेकिन एक एथलीट से बात करने पर ऐसा लगता है कि बैनर सिर्फ एक पेंट जॉब हैं, सरकार की कमियों को छुपाने के लिए। राजौरी गार्डन में रहने वाले 22 वर्षीय भांबरी ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार कभी मेरी मदद के लिए नहीं आई। मुझे कभी कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। पोस्टर लगाए गए हैं, दिल्ली बोले जीत के आना, कैसे जीत के आना? (दिल्ली कहती है ओलंपिक में पदक जीतो। इस तरह कैसे जीतें?) सार्थक ने आगे कहा, मैंने कहीं देखा है कि ओलंपिक के लिए होर्डिंग और पोस्टर पर करोड़ों खर्च किए गए हैं। यहां तक कि अगर उन्होंने हमें ओलंपिक में जाने से महीनों पहले हमारी तैयारियों के लिए 10-15 प्रतिशत भी दिया, तो हम इसे अपने प्रदर्शन पर अच्छे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। भांबरी और जैकब 400 मीटर रिले दस्ते के सदस्य थे, जिन्होंने 3:00:25 मिनट के समय के साथ ओलंपिक में एशियाई रिकॉर्ड बनाया, जैकब के साथ, जो मुख्य टीम का हिस्सा थे, दौड़ते समय 44.68 सेकेंड का सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय लगाते थे। दिल्ली सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी के शीर्ष एथलीटों की वित्तीय सहायता के लिए एक मिशन उत्कृष्टता योजना चला रही है। हालांकि, कई राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले प्रदर्शन के बाद भारत की 400 मीटर रिले टीम में जगह बनाने वाले भांबरी ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है।

उद्यमिता की शिक्षा

युवाओं के लिए यहां का बाजार एक बड़े मौके की तरह है

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर उद्यमिता की शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के लिए यहां का बाजार एक बड़े मौके की तरह है। एंटरप्रेन्योरशिप के हुनर को तराशकर मनपसंद फील्ड में मन से काम करके तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। आखिर आसानी से कैसे बढ़ें इस राह पर, बता रहे हैं हम...

हाल में उत्तर प्रदेश में चपरासी पद की मात्र 368 रिक्तियों के लिए 23.25 लाख आवेदन आना अखबारों की सुर्खियां तो बना ही, इससे राज्य सरकार का संबंधित विभाग भी इस बात को लेकर हैरान-परेशान हो गया कि आखिर इतने आवेदकों का साक्षात्कार लिया कैसे जाएगा। देश में बेरोजगारी की हालत बयां करने वाला इससे जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है। उक्त पद के लिए जहां न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास है, वहीं आवेदन करने वाले 1.53 लाख स्नातक, 25 हजार स्नातकोत्तर के साथ-साथ 250 पीएचडी भी हैं। सबका साक्षात्कार लेने में होने वाली असुविधा को देखते हुए संबंधित विभाग इसके लिए लिखित परीक्षा लेने पर विचार कर रहा है, ताकि आवेदकों की स्क्रीनिंग की जा सके। हालांकि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में कुछ सरकारी पदों के लिए लाखों की संख्या में आवेदन मिलना कोई नई बात नहीं है। कुछ वर्ष पहले सफाई कर्मियों के लिए भी लाखों लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें हर वर्ग के कैंडिडेट शामिल थे।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में होने वाली सैन्य भर्तियों में उमड़ने वाली भारी भीड़ के कारण अक्सर भगदड़ और दंगे जैसी स्थिति देखी जाती रही है। पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1.5 लाख शिक्षा-मित्रों की नियुक्ति को रद्द करने के बाद पूरे प्रदेश में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस सबसे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो, सरकारी नौकरियों के लिए हमारे देश में जबर्दस्त क्रेज है। दूसरे, हमारे शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने की शिक्षा न मिलने के कारण ही ज्यादातर युवा सरकारी नौकरियों के पीछे भागते रहते हैं।

सरकारी नौकरी के पीछे

हमारे देश में हर साल तकरीबन 50 लाख युवा डिग्रियां लेकर निकलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, पीएसबी, पीएसयू, स्थानीय निकायों आदि में इतनी रिक्तियां नहीं होतीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सके। निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए उच्च क्षेणी का अपडेटेड हुनर होना चाहिए, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में सभी युवाओं नहीं मिल पा रहा। ऐसे में हर साल बेरोजगारों की संख्या में विस्फोटक इजाफा होता जा रहा है। सरकारी नौकरी न मिलने हर युवा अपना करियर बनाने या जीवन चलाने के लिए उपयुक्त नौकरी की तलाश करता है। कई बार उन्हें अपने मन का काम मिल जाता है और कई बार नहीं भी। कभी-कभी उन्हें अपनी पसंद के विपरीत काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें काफी प्रयास के बाद भी नियमित नौकरी नहीं मिल पाती। जाहिर है कि जीवन चलाने के लिए इन्हें भी कुछ न कुछ तो करना ही है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में वक्त के साथ बदलाव न आना ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके लिए सरकारों और शिक्षा संस्थानों से समुचित कदम उठाने की उम्मीद की जाती है। कुछ संस्थानों ने तो प्रशंसनीय पहल की है, लेकिन यह अभी पर्याप्त नहीं है।

बदलाव की जरूरत

बढ़ती आबादी और बदलते वक्त की जरूरत को देखते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने और उसे रोजगारपरक बनाने की जरूरत है। रेगुलर कोर्सों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने वाले व्यावहारिक कोर्स भी शुरू किए जाने चाहिए। हाल के दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले स्टार्ट-अप्स की कामयाबी यह बताती है कि उद्यमिता के क्षेत्र में बेशुमार मौके हैं, बशर्ते कि सही सोच के साथ सही राह पर मन और मेहनत से काम किया जाए।

उद्यमिता क्रांति है विकल्प

भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में अगर स्कूली स्तर से ही बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाए, तो बड़े होने पर उन्हें सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अपनी स्किल की बदौलत उन्हें आसानी से नौकरी भी मिल सकती है और अपना काम शुरू करने की चाहत होने पर वे बैंकोंध्सरकारी संस्थाओं से लोन लेकर अपने कदम उद्यमिता की ओर बढ़ा सकते हैं। वैसे तो स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देश भर में अपने केंद्रों और सहभागी संस्थानों के जरिए विभिन्न कोर्स संचालित कर रहा है, लेकिन वक्त की जरूरत का देखते हुए अब हर संस्थान में ऐसे उपयोगी/व्यावहारिक केंद्रों की जरूरत है।

फैकल्टी भी हो प्रेरित

स्टूडेंट्स/युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए अध्यापकों को भी बदलना होगा। उन्हें समझना होगा कि शिक्षा संस्थानों से जुड़कर वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर स्टूडेंट्स को तराशने-निखारने की बड़ी जिम्मेदारी है। एक अध्यापक अपने पूरे करियर में हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाता और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। वह सिर्फ उन्हें परीक्षा पास कराने के लिए ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर ऐसे युवा गढ़ने की जिम्मेदारी होती है, जो देश और समाज को आगे ले जा सकें।

-सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय खुद को हुनरमंद बनाने की राह पर आगे बढ़ें। आज के समय में हर फील्ड में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। ऐसे में आप अपने पसंदीदा क्षेत्र को चुन कर उसमें अपने सपने पूरे कर सकते हैं।

-जिस भी क्षेत्र में अपने हुनर को तराशने की राह पर चलें, उसमें मन और मेहनत से प्रयास करें।

-हुनर को जीएंगे, उसमें डूबेंगे और मार्केट की जरूरत के अनुसार खुद को अपडेट रखेंगे, तो हर जगह आपकी मांग होगी।

कोरोनाकाल में एक उजले सेवापूर्ण करियर के रूप में उभरकर आया

नर्सिंग

इन दिनों नर्सिंग एक उजले सेवा पूर्ण करियर के रूप में उभरकर सामने आया है। यह एक ऐसा करियर है, जो गांवों की युवतियों से लेकर महानगरों की युवतियों तक करियर की एक समान संभावनाएं प्रस्तुत करता है। नर्स का कार्य मानवीय भावना से ओत-प्रोत कार्य है, जिसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। न सिर्फ रोगियों को स्वस्थ करने में बल्कि उनके प्राणों की रक्षा करने में भी नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? एक कुशल नर्स रोगियों की भावनाओं एवं मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझकर उनकी उचित देखभाल कर सकती है। इसलिए नर्सिंग युवतियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं निरापद करियर है। नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी काफी बढ़ गए हैं। सामान्यतया विवाहित युवतियों को नर्सिंग के कोर्स में प्रवेश की अनुमति नहीं है। नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात वह विवाह करने हेतु पूर्ण स्वतंत्र है। नर्सिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद नर्स के पद पर नियुक्त होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे कई निजी अस्पतालों में सेवा भावना के साथ रोजगार चाहने वाली महिलाओं को नर्सिंग का काम सिखाकर व अनुभव देकर नर्स बना दिया जाता है। नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए देश के सभी बड़े शहरों में नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं।

नर्सिंग के क्षेत्र में कई प्रकार के पाठ्यक्रम कराए जाते हैं किंतु बीएससी (नर्सिंग) कोर्स के प्रति युवतियों में विशेष आकर्षण है। बीएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि का है। जिसमें प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट अथवा 10.2 परीक्षा भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान विषय सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10.2 अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में कम-से-कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

चयन प्रवेशः परीक्षा के आधार पर होता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो युवतियां नर्सिंग के क्षेत्र में अध्यापन को करियर बनाना चाहती हैं, बीएससी (नर्सिंग) करने के पश्चात एमएससी (नर्सिंग) कर सकती हैं, जो दो वर्ष का पाठ्यक्रम है। चयन प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होता है। इसके अलावा नर्सिंग के क्षेत्र में नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एवं ऑजीलरी नर्सिंग प्रमुख पाठ्यक्रम हैं।

जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 10.2 अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े तीन वर्ष है, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है। ऑजीलरी नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश हेतु मैट्रिकुलेशन अथवा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अलग-अलग संस्थानों में पाठ्यक्रम की अवधि अलग-अलग होती है।

आमतौर पर यह पाठ्यक्रम डेढ़ वर्ष का होता है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से पत्राचार द्वारा तीन वर्षों का बीएससी (नर्सिंग) का पाठ्यक्रम किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 10+2 अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान समूह से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

ऑनलाइन ट्यूशन के क्षेत्र में बनाईए करियर

इसके आपके लिए संभावनाएं हैं अपार

पिछले कुछ समय में देश में बच्चों के पढ़ने का तरीका काफी बदल गया है। वैसे तो भारत में ऑनलाइन टीचिंग काफी समय से पॉपुलर है, लेकिन कोरोना काल ने इसे काफी बढ़ावा दिया है। लंबे समय से स्कूल बंद है और बच्चे घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ट्यूशन भी आस-पड़ोस में ना रहकर ऑनलाइन अधिक होने लगी है। कुछ समय पहले तक ऑनलाइन ट्यूटर दूसरे राज्य या दूसरे देश के बच्चों को कंप्यूटर की मदद से पढ़ाया करते थे। लेकिन अब तो अधिकतर घरों में अभिभावक ऑनलाइन ट्यूटर को ही हायर करते हैं। जिसके कारण इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। अगर आप भी इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो पढ़िए यह लेख...।

क्या होता है काम

एजुकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन वास्तव में होम ट्यूशन का ही एक एडवांस मैथड है। इसमें ई-ट्यूटरिंग के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग का मूल लाभ यह है कि ट्यूटर छात्र को किसी भी स्थान से, यहां तक कि वह अपने घर पर रहकर भी टीचिंग कर सकता है। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान समय को पहले से ही सुनिश्चित किया जाता है और फिर ऑनलाइन क्लासरूम में छात्र व टीचर मिलते हैं और पढ़ते व पढ़ाते हैं। इस नौकरी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने समय के अनुसार, पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर चुन सकते हैं। इसके अलावा यह आय का एक अच्छा स्रोत प्रदान करता है।

योग्यता

करियर एक्सपर्ट की मानें तो एक ऑनलाइन ट्यूटर के पास विशेषज्ञता के आधार पर योग्यता होनी आवश्यक है। मसलन, आप किसी विशेष भाषा के ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको उस भाषा से संबंधित कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा, बीएड, एमएड या नेट,आदि के बाद भी आप शिक्षण के क्षेत्र को चुन सकते हैं।

पर्सनल स्किल्स

एक ऑनलाइन ट्यूटर बनने के लिए सबसे जरूरी स्किल है पढ़ाई के प्रति जुनून। अर्थात् ना सिर्फ आपको दूसरों को पढ़ाना पसंद होना चाहिए, बल्कि खुद भी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत होनी चाहिए। चूंकि आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इसलिए आपमें तकनीकी गुण भी होने चाहिए। मसलन, कंप्यूटर व इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ-साथ बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन आदि भी बनाने आने चाहिए। इसके अलावा, ऑनलाइन टीचिंग के दौरान आपके कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अहम् हैं।

ऐसे बनें ऑनलाइन ट्यूटर

ऑनलाइन ट्यूटर बनने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अब तक ट्यूशन पढ़ाते आए हैं तो अब आप उन्हीं बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने की शुरूआत कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसी कई कंपनियां व वेबसाइट हैं, जो टीचर्स को हायर करके ऑनलाइन पढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे में आपको ऑनलाइन छात्र ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बस इन कंपनियों के साथ जुड़कर आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं।

आमदनी

ऑनलाइन ट्यूशन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर अनुभवी टीचर्स काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। शुरूआत में एक टीचर करीबन 200 रूपए प्रति घंटा चार्ज कर सकते हैं। वहीं कुछ समय के अनुभव, बाद आप 500 रूपए प्रति घंटा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र में अपनी क्वालिटी को साबित करते हैं और छात्रों को आपके पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तब आप की कमाई की कोई सीमा नहीं है।

ट्रांसलेशन में बनाएं बेहतर भविष्य

अनुवाद वह विधा है जो दो भिन्न भाषा-भाषी लोगों का एक-दूसरे से परिचय कराती है। अनुवाद ही अनजान भाषा की रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलती है। पहले अनुवादक एक सीमित करियर था लेकिन भू-मंडलीकरण के चलते जिस तरह दुनिया में आपसी संपर्क बढ़ा है, उससे अनुवादक का करियर भी संभावनाओं से लबरेज हो चुका है। पहले जहां अंग्रेजी, फ्रैंच, रूसी जैसी कुछ सीमित भाषाओं में नौकरी की संभावनाएं थीं वहीं आज दर्जनों भाषाओं खासकर चीनी, जापानी, जर्मन आदि में भी बड़ी अच्छी संभावनाएं पैदा हुई हैं। सरकारी नौकरियों में कनिष्ठ और वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों की संभावनाएं रहती हैं। अनुवादक बनने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

शैक्षणिक योग्यता

अनुवाद में डिप्लोमाध/सर्टीफिकेट या एम.फिल. करने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर होनी जरूरी है। साथ ही स्नातक स्तर पर हिंदी तथा अंग्रेजी एक विषय के रूप में अथवा स्नातक स्तर तक हिंदी माध्यम से अध्ययन किया हो। एक योग्य अनुवादक बनने के लिए विभिन्न संस्थान जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, उनमें प्रवेश के लिए लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षाओं को पास करना जरूरी होता है। प्रवेश पाने के लिए विभिन्न संस्थान हर सत्र में ऐसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इनमें हिस्सा लेने के लिए अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ आवेदन की जरूरत होती है। अनुवादक होने की डिग्री या डिप्लोमा मिलने के बाद केन्द्रीय सचिवालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी नौकरी मिलती है।

वेतनमान

प्राइवेट संस्थानों और बहुराष्ट्रीय निगमों में काम करने के लिए कोई निर्धारित वेतनमान नहीं होता। यह कंपनी की आर्थिक हैसियत और आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। अनुवादक को फुटकर काम बहुत मिलता है जैसे विभिन्न दूतावासों, चैनलों, पत्रिकाओं और अखबारों से लेकिन जहां तक सरकारी नौकरी के अंतर्गत कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के वेतन का सवाल है तो इस पद के लिए 3,050-4,590 रुपए तक का मूल वेतन दिया जाता है। जैसे-जैसे कर्मचारी कनिष्ठता से वरिष्ठता की ओर अग्रसर होता है वैसे-वैसे उसके वेतनमान में बढ़ौतरी होती रहती है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

तुर्की ने 76 संदिग्धों को हिरासत में लिया, 4,122 कलाकृतियां जब्त कीं

अंकारा । तुर्की के अधिकारियों ने देश और विदेश में बड़े पैमाने पर तस्करी विरोधी अभियानों में 76 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और 4,122 ऐतिहासिक कलाकृतियां जब्त की हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य द्वारा संचालित टीआरटी ब्रॉडकास्टर के अनुसार, तुर्की के 30 प्रांतों में 108 पतों पर कलेक्टरों सहित 92 संदिग्ध तस्करों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक उनमें से 76 को हिरासत में लिया गया है। टीआरटी ने कहा, तुर्की, बुल्गारिया, क्रोएशिया और सर्बिया में कई पतों पर किए गए चार अलग-अलग छापों में अनातोलिया नामक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, 4,122 ऐतिहासिक कलाकृतियों को जब्त कर लिया गया है। तुर्की के अभियोजकों ने कथित तौर पर यह निर्धारित करने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था कि एक संगठित अपराध संगठन ने अवैध रूप से तुर्की से ऐतिहासिक कलाकृतियों को अमेरिका और यूरोप में नीलामियों में बेचने के लिए स्थानांतरित कर दिया था।

आयरलैंड ने अनिवार्य होटल क्वारंटीन सूची में कजाकिस्तान को शामिल किया

डुबलिन। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आयरलैंड ने मध्य एशियाई देश में कोविड -19 स्थिति के कारण कजाकिस्तान को अपनी अनिवार्य होटल क्वारंटीन सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने विभाग के हवाले से कहा है कि जिन लोगों को पिछले 14 दिनों में कजाकिस्तान में पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है या उन्हें स्थानांतरित किया गया है, उन्हें सरकार द्वारा नामित होटलों में 14 दिनों के लिए आयरलैंड में आने पर अपने खर्च पर क्वारंटाइन होना होगा। 14-दिवसीय क्वारंटाइन की औसत लागत लगभग 2,000 यूरो (2,350 डॉलर) है। विभाग ने कहा कि यह फैसला शुक्रवार सुबह चार बजे से लागू होगा। जो लोग क्वारंटाइन होने से इनकार करते हैं या निर्धारित होटल से पहले छोड़ देते हैं, उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार जुमार्ना या कारावास, या दोनों का सामना करना पड़ेगा। अनिवार्य होटल क्वारंटाइन पहली बार देश में इस साल मार्च के अंत में पेश किया गया था। कुल मिलाकर, 30 देश और क्षेत्र अनिवार्य होटल क्वारंटाइन सूची में है।

सैन्य अभ्यास को लेकर किम जोंग-उन की बहन ने साउथ कोरिया, अमेरिका की खिंचाई की

सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने मंगलवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आलोचना की और जवाब में प्योंगयांग के परमाणु हथियार बनाने का संकल्प लिया। प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) द्वारा दिए गए एक बयान में, किम यो-जोंग ने कहा, वे (अभ्यास) अमेरिकी शत्रुतापूर्ण नीति की सबसे ज्वलंत अभिव्यक्ति हैं, जो हमारे राज्य को बल से दबाने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह एक अवांछित कार्य है। आत्म-विनाश के लिए एक महंगी कीमत चुकानी चाहिए क्योंकि वे हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति को और ज्यादा संकट में डालते हैं। हम अमेरिका से लगातार बढ़ते सैन्य खतरों, यानी राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं और हमारे खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का तेजी से मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली पूर्व-खाली हड़ताल से निपटने के लिए पूर्ण क्षमता के निवारक को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रेरणा देंगे। सियोल की योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि अभ्यास की निंदा करने के अलावा, उन्होंने दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी बलों को वापस बुलाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, प्रायद्वीप पर शांति स्थापित करने के लिए, अमेरिका के लिए दक्षिण कोरिया में तैनात अपने आक्रामक सैनिकों और युद्ध हार्डवेयर को वापस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, जब तक अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया में रहती है, कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थिति के समय-समय पर बिगड़ने का मूल कारण कभी खत्म नहीं होगा।

बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों के लिए अनिवार्य टीकाकरण का समर्थन किया

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह रक्षा विभाग (डीओडी) द्वारा 15 सितंबर तक देश की सेना के सभी सदस्यों के लिए कोविड -19 टीकाकरण अनिवार्य करने के प्रयास का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। डीओडी द्वारा सचिव ऑस्टिन के ज्ञापन का अनावरण करने के कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा कि मैं (रक्षा) सचिव (लॉयड) ऑस्टिन के संदेश का समर्थन करता हूं कि रक्षा विभाग ने आज मध्य सितंबर से पहले हमारे सेवा सदस्यों के लिए आवश्यक टीकाकरण की सूची में कोविड 19 वैक्सीन को जोड़ने की योजना बनाई है। इससे पहले दिन में, ऑस्टिन ने मेमो में कहा था कि वह सितंबर के मध्य में टीकों को अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग करेंगे। फाइजर वैक्सीन के लिए एफडीए की पूर्ण स्वीकृति के अभाव में, जो अब केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है, ऑस्टिन को वर्दी में पुरुषों और महिलाओं के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने के लिए बिडेन से छूट लेनी होगी। पेंटागन का निर्णय बाइडेन द्वारा घोषणा किए जाने के एक हफ्ते बाद आया। उन्होंने विभाग को यह देखने के लिए निर्देशित किया था कि वे हमारे सशस्त्र बलों को टीकाकरण की सूची में कोविड -19 को कैसे और कब जोड़ेंगे। बाइडेन के बाद सक्रिय ड्यूटी सैनिकों के बीच अनिवार्य टीकाकरण पर चर्चा तेज हो गई, जबकि पेंटागन को सुझाव देते हुए, जुलाई के अंत में घोषणा की गई कि कार्यकारी शाखा में सभी संघीय नागरिक कर्मचारियों को उनके टीकाकरण की स्थिति, नियमित परीक्षण, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ आधिकारिक यात्रा पर प्रतिबंध के अधीन होना आवश्यक है। पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार, 10 लाख से अधिक सैनिकों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और अन्य 237,082 को एक शॉट मिला है।

गैर-जिम्मेदार ताकतों की वापसी से अफगानिस्तान में होगी अशांति

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की गैरजिम्मेदाराना वापसी से आतंकवादियों को फायदा हो सकता है और देश में अशांति और बढ़ सकती है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कुरैशी ने उग्रवादी तत्व को कहर ढाने और क्षेत्र के लिए अराजक स्थिति पैदा करने के लिए एक शून्य छोड़ने के बिना सैनिकों की एक जिम्मेदार और व्यवस्थित वापसी का आह्वान किया। उन्होंने वापसी की प्रक्रिया के दौरान अफगानिस्तान में हिंसा के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। कुरैशी ने उल्लेख किया कि अफगान शांति प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में है, और एक अफगान-नेतृत्व वाली और अफगान-स्वामित्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यापक-आधारित और समावेशी समाधान खोजने की सख्त आवश्यकता है। अफगानिस्तान में अशांति के कारण अपने देश द्वारा किए गए बलिदानों को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देश में युद्ध का शिकार रहा है। हमने जो कीमत चुकाई है, उसे समझना होगा। हमें करीब 80,000 लोग हताहत हुए हैं, हमें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दुनिया को इससे बेखबर नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान शांति और सुलह प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई है और अब यह अफगान नेतृत्व पर निर्भर है कि वह अंतर-अफगान वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अपने देश के प्रयासों के बारे में बात करते हुए, कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में तालिबान को वार्ता की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने फरवरी 2020 में दोहा में यूएस-तालिबान शांति समझौते के समापन की सुविधा प्रदान की। अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीयसमुदाय पर जोर देते हुए, कुरैशी ने कहा कि दुनिया को यह महसूस करना चाहिए कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता एक साझा जिम्मेदारी है और अंतर्राष्ट्रीय

समुदाय इससे दूर नहीं हो सकता है और अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका देश अफगान सीमा के रास्ते पाकिस्तान से आने और जाने वाले लोगों की जांच करना सुनिश्चित कर रहा है, जबकि उन्होंने सीमा पर बाड़ लगाने का 98 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।

अमेरिकी रक्षा सचिव ने पाकिस्तानी सेना जावेद बाजवा के साथ अफगान स्थिति पर चर्चा की

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सोमवार को अफगानिस्तान के हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का ब्योरा देते हुए बताया, ''रक्षा मंत्री ऑस्टिन और जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता तथा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की।'' उन्होंने बताया कि ऑस्टिन ने बाजवा के साथ क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के परस्पर लक्ष्यों पर भी चर्चा की।

किर्बी के मुताबिक, ''बातचीत के दौरान ऑस्टिन ने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में सुधार जारी रखने की बात कही।'' अमेरिका और नाटो के सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का हमला बढ़ गया है और उसने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के हमलों के बाद अफगान सुरक्षा बलों ने अमेरिका के साथ मिलकर हवाई हमले की कार्रवाई भी की है। अफगानिस्तान और अमेरिका ने तालिबान लड़ाकों को पनाह देने और अन्य सहायता मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। अफगानिस्तान में दशकों से चल रहे गृह युद्ध के कारण करीब 20 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और अफगान सरकार के साथ राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए वार्ता को लेकर उसने तालिबान पर दबाव बनाया।

रूस ने जवाबी कार्रवाई में ब्रितानियों पर प्रतिबंध लगाया

मॉस्को (एजेंसी)।

रूस सरकार ने घोषणा की है कि उन्होंने कथित मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के लिए ब्रिटेन द्वारा रूसियों के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में देश में ब्रिटिश नागरिकों की एक आनुपातिक संख्या में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह स्वीकृत रूसी विरोधी गतिविधियों में निकटता से शामिल हैं और रूसी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, उनके नाम का खुलासा किए बिना और कितने लोगों को लक्षित किया गया है। समाचार एजेंसी ने मंत्रालय के हवाले से कहा कि मास्को लंदन के आधारहीन हमलों को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और रूसी न्यायिक प्रणाली पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखता है।

इसमें कहा गया है, हम एक बार फिर ब्रिटिश नेतृत्व से अपने देश के संबंध में एक निराधार टकराव की नीति को छोड़ने का आह्वान करते हैं। कोई भी अमित्र कदम पर्याप्त आनुपातिक प्रतिक्रिया को पूरा करेगा। दिसंबर 2020 में, यूके ने तीन रूसियों और टेरेक स्पेशल रैपिड रिस्पांस यूनिट के खिलाफ चेचन्या में एलजीबीटी लोगों के खिलाफ यातना और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जमा कर दी है।

रेड क्रॉस ने 10 दिनों में 4,000 से अधिक घायल अफगानों का इलाज किया

काबुल (एजेंसी)।

रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने युद्धग्रस्त देश में बढ़ते संघर्ष के बीच 15 आईसीआरसी समर्थित स्वास्थ्य सुविधाओं से 1 अगस्त से अब तक कुल 4,042 घायल अफगान नागरिकों का इलाज किया है। अफगानिस्तान में आईसीआरसी के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एलोई फिलियन ने समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा कि हम देख रहे हैं कि घरों को नष्ट कर दिया गया है, चिकित्सा कर्मचारियों और रोगियों को भारी जोखिम में डाल दिया गया है, और अस्पतालों, बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचा है। शहरों में विस्फोटक हथियारों के उपयोग का जनसंख्या पर अंधाधुंध प्रभाव पड़ रहा है। कई परिवारों के पास सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसे रोकना चाहिए। आईसीआरसी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में कुंदुज, लश्कर गाह और अन्य शहरों में सड़क की झड़पों में सैकड़ों नागरिक घायल हो गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान और कर्मचारियों की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं पर भारी दबाव है। कई विवादित शहरों में बिजली गुल है और कुछ जगहों पर पानी की आपूर्ति प्रणाली मुश्किल से चालू है। इसमें कहा गया है कि कई परिवार स्थान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचने के लिए परिवहन नहीं मिल रहा है या उनके पास वित्तीय साधन नहीं हैं। आईसीआरसी और उसके सहयोगी अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी घायलों को निकालने और संघर्ष के परिणामस्वरूप मारे गए लोगों के नश्वर अवशेषों को ले जाने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। अकेले जुलाई में,आईसीआरसी ने देश भर में हथियार से संबंधित चोटों से पीड़ित लगभग 13,000 रोगियों की मदद की, और यह संख्या इस महीने बढ़ने की संभावना है क्योंकि अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में लड़ाई बढ़ रही है। रिपोर्ट में फिलियन के हवाले से कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, चिकित्सा कर्मचारियों और एम्बुलेंस को हर कीमत पर बख्शा जाना चाहिए। हम सभी लड़ने वाले दलों से भी आवाहन करते हैं कि वे आईसीआरसी और एआरसीएस जैसे मानवीय संगठनों को घायलों को सुरक्षित निकालने और नागरिक आबादी को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करने की अनुमति दें।

पाकिस्तान में मंदिर की मरम्मत के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय को सौंपा गया, 90 लोगों को किया गया गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

लाहौर। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को कहा कि पंजाब प्रांत में भीड़ के हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मंदिर की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस मामले में कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर स्थित प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग कस्बे में गत बुधवार को एक मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने एक स्थानीय मदरसे को कथित तौर पर अपवित्र करने के लिए गिरफ्तार किए गए आठ वर्षीय हिंदू लड़के को अदालत द्वारा रिहा करने के विरोध में मंदिर पर हमला किया था।

रहीम यार खान जिले के पुलिस अधिकारी असद सरफराज ने को सोमवार को कहा, '' सरकार ने मंदिर की

मरम्मत का काम पूरा कर लिया है और इसे स्थानीय हिंदू समुदाय के हवाले कर दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि यह पूजा-अर्चना के लिए तैयार है। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में पूछे जाने पर सरफराज ने कहा, ''वीडियो फुटेज की मदद से कुल 90 संदिग्धों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।'' अधिकारी ने बताया कि मुख्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हैदराबाद के लोगों को भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंपा है। इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदारी ने मंदिर पर हुए हमले को ''शर्मनाक'' करार देते हुए बताया था कि पुलिस ने मामले में 50 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मंदिर पर हमला करने के आरोप में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ आतंकवाद और पाकिस्तान दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यूएस डेमोक्रेट्स ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की योजना का अनावरण किया

वाशिंगटन (एजेंसी)।

यूएस डेमोक्रेट्स ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की बजट योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिपब्लिकन समर्थन के बिना राष्ट्रपति जो बाइडन के सामाजिक-खर्च के अधिकांश एजेंडे को लागू करना है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को सीनेट के बहुमत के नेता चक शूमर ने एक पत्र में डेमोक्रेट्स को बताया कि कांग्रेस का लक्ष्य 15 सितंबर तक सदन के अगस्त के अवकाश से लौटने से पहले कानून लिखना है। सीनेट के 50-50 के विभाजन के साथ, डेमोक्रेट्स को नरमपंथियों को रखना चाहिए, जो एजेंडा के तत्वों का विरोध कर सकते हैं और बजट सुलह के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खर्च करने वाले बिल को मंजूरी दे सकते हैं। यह कदम तब आया जब सीनेट ने लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के द्विदलीय बुनियादी ढांचे के बिल को पारित करने के करीब है और ऊपरी सदन ने सप्ताहांत में बिल को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करने के लिए मतदान किया। व्हाइट हाउस और सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने महीनों की बातचीत के बाद बुनियादी ढांचे के बिल पर एक समझौता किया, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नए खर्च में 550 अरब डॉलर शामिल हैं। बुनियादी ढांचे की बातचीत के साथ, शूमर और अन्य डेमोक्रेटिक नेता रिपब्लिकन समर्थन के बिना एक अलग बिल में 3.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की योजना को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसे दो-ट्रैक रणनीति कहते हैं। शूमर ने कहा कि चैंबर मंगलवार को जैसे ही द्विदलीय बुनियादी ढांचे की योजना को मंजूरी देगा और फिर तुरंत डेमोक्रेट-केवल बजट उपाय पारित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सोमवार को एक ट्वीट में, शूमर ने कहा कि डेमोक्रेटिक बजट अमेरिकियों के लिए लागत कम करेगा और अमेरिकी परिवारों के लिए करों में कटौती करेगा, जलवायु संकट से निपटने के दौरान लाखों नौकरियां पैदा करेगा और यह अमीरों और निगमों द्वारा उनके उचित हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर आईपीसीसी की रिपोर्ट ने किया आगाह, मानवता के लिए बताई ख़तरे की घंटी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे व्यापक और तीव्र जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जैसा पिछले हजारों सालों में नहीं देखा गया है और इसके प्रभाव से सदी में 4 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक गर्म हो सकता है। सोमवार को जारी किए गए आकलन में जंगलों में आग, बाढ़ और सूखे जैसी चरम सीमाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन इसका कहना है कि उत्सर्जन में गहरी और तीव्र कटौती करने से ऑस्ट्रेलिया और दुनिया को सबसे गंभीर पृथ्वी ताप और इससे जुड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। 1988 में आईपीसीसी की स्थापना के बाद से यह इसकी छठी रिपोर्ट है और किसी भी पिछले संस्करण की तुलना में अधिक क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करती है। यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देती है कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन कैसे होगा।

यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में वास्तविक रूप से सामने आए हैं। इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट का क्षेत्र शामिल है, जहां महासागर वैश्विक औसत से चार गुना से अधिक की दर से गर्म

हो रहा है। हम ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुमानों, जलवायु प्रभावों और कार्बन बजट में विशेषज्ञता वाले जलवायु वैज्ञानिक हैं। हम पिछले तीन वर्षों में आईपीसीसी रिपोर्ट तैयार करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा रहे हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि मध्यम उत्सर्जन होने पर भी, आने वाले वर्षों और दशकों में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव काफी खराब होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की एक डिग्री का हर अंश कई चरम सीमाओं की आशंका और गंभीरता को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का हर प्रयास मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया निस्संदेह गर्म हो रहा है 1910 के बाद से ऑस्ट्रेलिया लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है।

आईपीसीसी के आकलन का निष्कर्ष है कि मानव गतिविधियों से वातावरण में अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों के हिसाब के बिना ऑस्ट्रेलिया और विश्व स्तर पर वार्मिंग की सीमा को समझाना असंभव है। रिपोर्ट जलवायु प्रभाव-चालकों (सीआईडी) की अवधारणा के बारे में बताती हैं- 30 जलवायु औसत, चरम सीमाएं और घटनाएं जो जलवायु प्रभाव पैदा करती हैं। इनमें गर्मी, सर्दी, सूखा और बाढ़ शामिल हैं। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ग्लोबल वार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्म तापमान की तीव्रता और आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है, साथ ही लगभग सभी तरह के शीत चरम में कमी आई है। आईपीसीसी ने पूरे विश्वास के साथ इस बात का उल्लेख किया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी की घटनाएं, मानवीय प्रभाव के कारण अधिक संभावित या अधिक गंभीर बनीं। इन घटनाओं में शामिल हैं- 2012-13 की ऑस्ट्रेलियाई गर्मी, जिसे एंग्री समर के रूप में भी जाना जाता है, जब ऑस्ट्रेलिया के 70त्न से अधिक लोगों ने अत्यधिक तापमान का अनुभव किया 2014 में ब्रिस्बेन हीटवेव 2018 क्वींसलैंड की आग से पहले की अत्यधिक गर्मी 2019-20 की भीषण गर्मी जो ब्लैक समर झाड़ियों में आग का कारण बनी।

अमेरिका के रक्षा विभाग का बयान, भारत ने अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने सोमवार को कहा कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' भारत ने अतीत में प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है।'' अफगानिस्तान पर भारत और अमेरिका के सहयोग के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, '' अफगानिस्तान में स्थिरता तथा सुशासन के लिए इस तरह के काम, इस तरह के प्रयासों का हमेशा स्वागत किया जाता है।''

किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उस सीमा पर मौजूद सुरक्षित पनाहगाहों के बारे में पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रखी है। उन्होंने कहा, '' हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि वे सुरक्षित पनाहगाह अफगानिस्तान के अंदर केवल अधिक असुरक्षा तथा अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी नेताओं के साथ इस पर चर्चा को लेकर हिचकिचाते नहीं हैं। हमारा ध्यान इस ओर भी है कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों का शिकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी हो रहे हैं। इसलिए, हम इस बात को लेकर सहमत हैं कि तालिबान या अन्य आतंकवादी नेटवर्क को सुरक्षित पनाहगाहों का इस्तेमाल ना करने दिया जाए और इन्हें बंद किया जाए। इस बारे में हम पाकिस्तान से लगातार बात कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ल्यॉड ऑस्टिन का कहना है कि अफगानिस्तन में सुरक्षा स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है, जिस पर स्पष्ट तौर पर सही दिशा में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, '' मंत्री का मानना है कि अफगान बलों में बदलाव लाने की क्षमता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

होटल के पार्किंग से 66 लाख के गांजा समेत 2 शख्स गिरफ्तार

क्रांति समय दैनिक

सूरत,जिले के बारडोली में माणेकपोर हाईवे स्थित एक होटल के पार्किंग से पुलिस ने 661 किलो गांजा के साथ दो शख्सों को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी और एलसीबी की संयुक्त कार्यवाही में गांजा सेत कुल 77.47 लाख रूपए का मुद्दामाल जब्त किया गया है। गांजा भेजने वाले और लेने वाले को वांटेड घोषित कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरूकी। सूरत जिला पुलिस अधीक्षक उषा राडा ने नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाओं को सख्ती से कुचलने का आदेश दिया है। इसके अंतर्गत एलसीबी पीआई बीके खाचर और एसओजी पीआई केजे धडूक के मार्गदर्शन में पुलिस जवान कार्यरत थे। इस बीच एलसीबी को सूचना मिली कि उडीसा से बड़े टेम्पो में गांजा लाया गया है और यह टेम्पो सूरत जिले की बारडोली तहसील के माणेकपोर गांव स्थित सहयोग होटल की

पार्किंग में खड़ा है। सूचना के आधार पर एसओजी और एलसीबी सहयोग होटल पहुंच गई। टेम्पो में 661 किलो गांजा लदा हुआ था। पुलिस ने टेम्पो के ड्राइवर 34 वर्षीय दिवाकर कृष्णचंद्र बहेरा और क्लीनर 37 वर्षीय सुशांत बनमाली प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े दोनों आरोपी उड़ीसा उडीसा के मूल निवासी हैं। पुलिस ने घटनास्थल से रु 6610000 कीमत के 661 किलो गांजा, रु 28740 नकद, दो मोबाइल और टेम्पो समेत कुल 7447240 रूपए का माल-सामान जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उड़ीसा के गंजाम जिले से गांजा लाए थे और इसकी डिलीवरी सूरत में की जानी थी। सहयोग होटल में गांजा की डिलीवरी लेने आनेवाले शख्स की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुलिस ने गांजा भेजने और लेने वालों को वांटेड घोषित कर आगे की कार्रवाई शुरूकी है।

गिरफ्तार आरोपितों के नाम व पते

दिवाकर कृष्णचंद्र बेहरा उम्र-34 रहे-समा गांव, बारापल्ली शाही, थाना-पुरुषोत्तमपुर, जिला-गंजम उड़ीसा।

सुशांत बनमाली मंत्री उम्र-37 रहे-समा गांव, बारापल्ली शाही, थाना-पुरुषोत्तमपुर, जिला-गंजम उड़ीसा

वांटेड- मारिजुआना के प्रेषक - रवींद्र बेहरा जिनका पूरा नाम ज्ञात नहीं है -समा गांव, बारापल्ली सही थाना पुरुषोत्तमपुर, गंजम उड़ीसा

वांटेड : अज्ञात आरोपी जिसका नाम और पता नहीं है।

जब्त संपत्ति का विवरण

भांग की मात्रा कुल-661 किलो चना, कीमत 66,10,000

आरोपी के शरीर के अंगों से मोबाइल नंबर 2 बरामद, कीमत 8,500 रुपये

आरोपियों के पास से 28,740 रुपये नकद बरामद

आयशर टेम्पो (GJ-06-YY-7355)

मामले की कुल कीमत 73,47,240 रुपये है

पुलिस हिरासत से फरार
दुष्कर्म और पोस्को का आरोपी देर रात सायण से गिरफ्तार

क्रांति समय दैनिक

सूरत,बीते दिन शहर के पांडेसरा पुलिस थाने से पुलिसकर्मी की धक्कार देकर फरार दुष्कर्म और पोस्को के आरोपी को पुलिस ने देर रात सायण की एक फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उस वक्त फरार हो गया जब उसे पुलिस कोर्ट ले जा रही थी। जानकारी के मुताबिक सूरत के पांडेसरा क्षेत्र में रहनेवाला रामचंद्र उर्फ राम चरण नामक शख्स ने 19 जून को मासूम बच्चे की मदद से मानसिक रूप से बीमार

एक किशोरी को अपने घर बुलाया था। जहां रामचंद्र उर्फ राम चरण ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना का खुलासा होने पर किशोरी के परिवार ने पांडेसरा

पुलिस थाने में रामचंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने पोस्को और दुष्कर्म का केस दर्ज कर 8 अगस्त को दो नाबालिग समेत मुख्य आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार किया था। बच्चों को जुवेनाइल होम भेजने के बाद 9 अगस्त को पांडेसरा पुलिस आरोपी रामचंद्र को कोर्ट ले जा रही थी। उस वक्त पांडेसरा पुलिस थाने के बाहर पुलिस जवान को धक्का मारकर आरोपी रामचंद्र फरार हो गया। दुष्कर्म और पोस्को के आरोपी की फरार होने से पुलिस बेडे में हडकम्प मच गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 100 पुलिसकर्मियों की 15 टीमें बनाई गईं। पांडेसरा पुलिस थाने के प्रभारी एपी चौधरी ने बताया कि आरोपी पांडेसरा पुलिस थाने से भागकर अलथाण खाडी और वहां से चलते चलते उधना दरवाजा पहुंचा था। जहां ऑटो रिक्शा में सवार होकर सायण की ओर भाग गया और वहां की एक फैक्ट्री में जाकर छिप गया था। इस संदर्भ में सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम सायण की फैक्ट्री में पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम जूनागढ़ में,मुख्यमंत्री करेंगे झंडारोहण

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद, इस बार स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह जूनागढ़ में आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जूनागढ़ में, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी वलसाड़ में और उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल पंचमहाल में जबकि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं कलक्टर विभिन्न जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों में आर.सी. फल्दू कच्छ जिले में, भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा सूरत में, कौशिकभाई पटेल साबरकांठा, सौरभभाई पटेल राजकोट, गणपतसिंह

वसावा दाहोद, जयेशभाई रादड़िया भावनगर, दिलीपकुमार ठाकोर भरुच, ईश्वरभाई पारमार गांधीनगर, कुंवरजीभाई बावालिया मेहसाणा और जवाहर चावड़ा जामनगर में झंडा फहराएंगे। वहीं, राज्य मंत्रियों में प्रदीपसिंह जाडेजा वडोदरा में, बचुभाई खाबड़ खेड़ा में, जयद्रथसिंह परमार सुरेन्द्रनगर, ईश्वरसिंह पटेल अमरेली, वासणभाई आहिर बनासकांठा, विभावरीबेन दवे अहमदाबाद, रमणलाल पाटकर नवसारी, किशोरभाई कानाणी छोटाउदेपुर, योगेशभाई पटेल आणंद और धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा मोरबी जिले में तिरंगा फहराएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की जानकारी के अनुसार डांग, पाटण, पोरबंदर, नर्मदा, तापी, बोटाद, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, अरवल्ली और महिसागर में संबंधित जिले के कलक्टर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे।

सार-समाचार

उप मुख्यमंत्री ने रेसीडेंट डॉक्टरों को गैरकानूनी बताते हुए काम पर लौटने की अपील की

अहमदाबाद,उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने आज फिर एक बार राज्य में चल रही रेसीडेन्ट डॉक्टरों की हड़ताल को गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें काम पर वापस लौटने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा कि बिना शर्त हड़ताल खत्म करने के बाद ही रेसीडेन्ट डॉक्टरों के साथ बात हो सकती है। काम पर लौटने के बाद ही उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा और इसके लिए डीन स्तर के अधिकारियों की समिति का गठन कर उचित मांगों पर विचार कर उचित फैसला किया जाएगा। नितिन पटेल ने कहा कि रेसीडेन्ट डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य के नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इंडोर-आउटडोर समेत ऑपरेशन सुविधाएं बदस्तूर जारी हैं। उन्होंने कहा कि पीजी डॉक्टरों के लिए परीक्षाएं राजकोट, भावनगर और जामनगर की यूनिवर्सिटी में समय पर ली गई थीं, जिससे इन शहरों में ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज समेत अन्य यूनिवर्सिटी की परीक्षा विलंब से होने के कारण अहमदाबाद समेत राज्य के अन्य केवल 250 जितने विद्यार्थियों की समस्या है। जिसे गलत तरीके से बड़ा स्वरूप देकर नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है, जो अनुचित है। उन्होंने एमबीबीएस और इन्टर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को हड़ताली डॉक्टरों के बहकावे में अपना भविष्य खराब नहीं करने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज रेसीडेन्ट डॉक्टरों की मांगों के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल जयप्रकाश शिवहरे, अतिरिक्त निदेशक-चिकित्सा शिक्षा समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन समेत सुप्रिटेन्डेन्ट के साथ विस्तार से प्रत्यक्ष और वर्च्युअल चर्चा की गई। यदि रेसीडेन्ट डॉक्टर बिना शर्त अपनी हड़ताल वापस लेते हैं तो उनके उचित मांगों के लिए डीन एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों, शिक्षक और अधिकारियों की पांच सदस्यों की टीम गठित करने का फैसला किया गया है। इस समिक्षि के समक्ष रेसीडेन्ट डॉक्टर अपनी प्रश्न पेश कर सकते हैं और समिति उचित विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट में के आधार पर ही राज्य सरकार कोई फैसला करेगी।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

चार अगस्त तक 456 गर्भवती महिलाओं को लगी कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक : सरकार

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले हफ्ते तक तीन लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि सिर्फ 456 गर्भवती महिलाएं ही ऐसी हैं, जिन्हें टीकों की दोनों खुराक दी गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ''कोविन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चार अगस्त 2021 तक कुल 3,05,938 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए हैं। इनमें से 3,05,482 लाभार्थी ऐसी हैं जिन्हें पहली खुराक लगी हैं वहीं 456 लाभार्थी ऐसी हैं जिन्हें दोनों खुराक दी जा चुकी हैं।'' पवार ने बताया कि इसी अवधि के दौरान अब तक कुल 91,104 खुराक ट्रांसजेंडरों को दी गई है। इनमें 77,457 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई है जबकि 13,647 लाभार्थियों को दोनों खुराक दी जा चुकी है।

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों का ग्रेनेड हमला, 5 लोग जख्मी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजकर 40 मिनट में एक संदिग्ध व्यक्ति ने एसएसबी के बंकर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। समाचार एजेंसी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में पांच नागरिक घायल हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए स्थानीय नागरिकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही ग्रेनेड हमला करने वालों की तलाश में इलाके में घेराबंदी की गई है। गौरतलब है कि शोपियां जिले में मंगलवार तड़के सीआरपीएफ के सड़क सुरक्षा दल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि क्रालचेक पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के सड़क सुरक्षा दल पर हमला किया।

आदिवासी गोंड समाज ने सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा

गोरखपुर। आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंड आदिवासी समाज के सभी महानायकों को समाजवादी अनूसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा याद किया गया। इसी क्रम में बेतियाहाता कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में गोंड समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकाला। गोलघर होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुँच जहाँ स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन लिया गया और बीएल मीना प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 26-03-2020 के शासन आदेश को पालन करने का आश्वासन दिया गया।

जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए : गुलाम नबी आजाद

श्रीनगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए भूमि और रोजगार के अधिकारों की वकालत की। कश्मीर के गांदरबल जिले के तुल्लामुल्ला क्षेत्र में खीर भवानी मंदिर परिसर के बाहर आजाद ने संवाददाताओं से कहा 1990 की शुरुआत में आतंकवाद के कारण घाटी से बाहर गए कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'चुनाव जल्दी कराना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए जो बेहद जरूरी है। कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाना चाहिए।' आजाद ने कहा, 'अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद हमारी भूमि और रोजगार (अधिकार) जो छीन लिए गए थे, उन्हें वापस दिया जाना चाहिए, उसी तरह जैसे वो पहले (पांच अगस्त 2019) थे। इसके लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद नया कानून लाया जाना चाहिए।' आजाद के मंदिर जाने से कुछ देर पहले सुबह राहुल गांधी वहां गए थे। आजाद जब तुल्लामुल्ला पहुंचे तब गांधी हजरतबल के लिए निकल चुके थे।

खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलना लोगों की इच्छा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खेल है : शिवसेना

मुंबई। शिवसेना ने सोमवार को कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लोगों की इच्छा नहीं, बल्कि एक ''राजनीतिक खेल'' है। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में आज प्रकाशित एक संपादकीय पूछा कि क्रिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है, जो अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। भारत में खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान 'खेल रत्न पुरस्कार' का नाम पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर था जिसे तोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीम के सराहनीय प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को बदलकर 'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि देशभर से नागरिकों ने उनसे खेल रत्न का नाम मेजर ध्यान चंद के नाम पर रखने का आग्रह किया था। शिवसेना ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आतंकवादी हमलों का शिकार हुए थे। नेताओं में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के विकास के लिए उनके बलिदान का इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। संपादकीय में कहा गया, 'राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यान चंद खेल रत्न करना लोगों की इच्छा नहीं , बल्कि एक राजनीतिक खेल है। मेजर ध्यानचंद का सम्मान, राजीव गांधी के बलिदान का अपमान किए बिना भी किया जा सकता था, लेकिन देश में इस तरह की परंपरा और संस्कृति समाप्त हो गई है। इससे ध्यानचंद भी स्वर्ग में दुखी हुए होंगे।'

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुष्कर्म और हत्या मामले में नाबालिग के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता को मंजूरी दी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली छावनी के पुराने नंगल इलाके के पास कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार 9 वर्षीय बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है।

सूत्रों ने बताया कि लड़की के परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपये के मुआवजे की मंजूरी दी है, जो लड़की के परिवार को प्रदान किया जाएगा। केजरीवाल ने चार अगस्त को परिवार से मिलने के दौरान आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। परिवार से मिलने के बाद केजरीवाल ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए थे, जिसमें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दिल्ली छावनी के पास एक श्मशान में चार लोगों ने 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या कर दी थी। केजरीवाल ने 4 अगस्त को नाबालिग के परिवार से मुलाकात के बाद कहा था, हम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देंगे और मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। दोषियों को सजा दिलाने के लिए शीर्ष वकीलों को लगाया जाएगा। केंद्र सरकार को दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, हम सहयोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने श्मशान के एक पुजारी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर बलात्कार, हत्या और धमकी के आरोप, पोक्सो अधिनियम और एससी / एसटी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लड़की के परिवार ने पड़ोसियों के साथ इलाके में (पंखा रोड पर) विरोध प्रदर्शन किया और चारों लोगों के लिए मौत की सजा और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र न्याय की मांग की। नौ साल की बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के चार आरोपियों को सोमवार को दिल्ली पुलिस की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान राधेश्याम (55), सलीम (55), लक्ष्मी नारायण (49) और कुलदीप (63) के रूप में हुई है।

मेरठ : दरोगा पर महिला मित्र के साथ मिलकर हनीट्रैप गैंग चलाने का आरोप , पुलिस ने खोला राज

श्रीनगर। (एजेंसी)।

मेरठ। मेरठ के स्सक्क प्रभाकर चौधरी के तेवरों से पुलिस विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति मची हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसएसपी लगातार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मेरठ के गंगानगर थाने में तैनात दरोगा दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि दारोगा एक युवती के साथ मिलकर हनीट्रैप गैंग चला रहा था। दोनों लोगों को फंसाकर रुपये ठगने का काम करते थे। मामले में दारोगा समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

16 जून 2021 को एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मेरठ में कप्तान के तौर पर जिले की कमान संभाली। एसएसपी ने पहले दिन ही पुलिस को साफ शब्दों में हिदायत दी थी कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी की भ्रष्टाचार के संबंध में कोई भी शिकायत या लापरवाही मिली तो सीधे मुकदमा दर्ज कर सस्पेंड किया जाएगा। एसएसपी लगातार पहले दिन से ही दागी पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कस रहे हैं, और उसके बाद भी मेरठ पुलिस शायद एसएसपी की नसीहत को समझ नहीं रही है। स्सक्क-72 पुलिसकर्मियों को एक दिन में ही लाइन हाजिर कर चुके हैं। गंगानगर थाने में दरोगा दिनेश कुमार रजपुरा चौकी पर तैनात थे। 2 माह पहले जहां एक युवक पर छेड़छाड़ के मामले में दरोगा युवक को थाने में ले आए, उस समय एसएसपी अजय साहनी मेरठ में कप्तान थे।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं है कोई व्यवस्था, प्रदेश का हर वर्ग परेशान है : कमलनाथ

भोपाल (एजेंसी)।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान पीड़ित है, मूल्य, खाद और बीज नहीं मिल रहा है। मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके आया, कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने घोषणा की कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है उन्हें मुआवजा देंगे। एक व्यक्ति को भी नहीं मिला।

इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा शुरू हुई, महंगाई पर प्रश्न उठा, हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था।सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई थी कि स्थगन प्रस्ताव में से एक तो स्वीकार कर लीजिए। हमने 139 में कई प्रस्ताव रखे थे उसमें से बता दीजिए कि 3-4 स्वीकार करेंगे।कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। आज उन्होंने पाखंड किया। इन्होंने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया और उनके साथ पाखंड किया। पिछड़ा वर्ग की पीठ में छूरा घोंपने की घटिया राजनीति की।

विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए योगी के अधिकारी लगाएंगे चौपाल

लखनऊ। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चुनाव की आहट होते ही हाथ पांव फूलने लगे हैं। अभी तक सरकार अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों का ढिंढोरा पीट रही थी लेकिन जैसे ही विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाया तो सरकार ने तुरंत ही अपने अधिकारियों की टीम को शहर से लेकर गांव-देहात की ओर रवाना कर दिया है। मकसद साफ है जो काम सरकार ने कराए हैं,उस की जमीनी हकीकत क्या है। यह पता किया जाए। कहीं ऐसा ना हो हो की अति आत्मविश्वास में योगी सरकार का भी वही हाल न हो जाए जैसा कभी %इंडिया शाइनिंग, का हुआ था। उस समय केंद्र की अटल सरकार इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी थी लेकिन इंडिया शाइनिंग का नारा चारों खाने चित हो गया था और अटल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता देखता पड़ गया था। इसीलिए योगी आदित्यनाथ केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का कितना लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, इसका सत्यापन अब प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से कराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं निरीक्षण शुरू करने के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है।

यह अधिकारी 14 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक विभिन्न ब्लाकों के अलग-अलग गांवों में जाकर विकास के काम का निरीक्षण और योजनाओं के क्रियान्वयन की सत्यापन करते हुए उसकी हकीकत जानेंगे। शहर क्षेत्र में भी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। निरीक्षण के बाद इन अधिकारियों को जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपनी होगी।जिन योजनाओं का क्रियान्वयन और सत्यापन होना है।उसमें ग्राम पंचायत में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ पेयजल, पशु टीकाकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, वृद्धावस्था/दिव्यांगजन/विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, पंचायत भवन, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा, मनरेगा द्वारा कराये गए कार्य आदि शामिल है।सभी जिलाधिकारियों ने अपने अधीन एसडीएम को निर्देश दिया है कि वे संपूर्ण समाधान दिवस एवं समाधान दिवस के बाद तहसील के किसी एक ग्राम पंचायत का निरीक्षण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन का सत्यापन करें। सभी एसडीएम को निरीक्षण का शेड्यूल जारी करने को भी कहा गया है।

शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण एवं सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण किए जाएंगे। अधिकारी वहां चौपाल भी लगाएंगे। इसके पीछे उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न वार्डों में चौपाल लगाने एवं निरीक्षण के लिए अधिकारियों को नामित किया है। ये अधिकारी 15 दिनों के भीतर जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगे।

गौतम गंभीर को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है भाजपा? ऐसे मिल रहे संकेत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने है। माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच होगी। इन सबके बीच सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल, हाल में ही पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के साथ भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद गौतम गंभीर को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

माना जा रहा है कि निगम चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव कर सकती है। दिल्ली में वर्तमान में आदेश गुप्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। उनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज तिवारी के पास थी। माना जा रहा है कि गौतम गंभीर लगातार केजरीवाल सरकार पर आक्रामक तेवर अपनाए रहते हैं। केजरीवाल सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदा विधेयक में लोग चाहते हैं 3 बच्चों का मानदंड

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने मसौदा कानून पर लोगों से मिले सुझावों को 53 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

इनमें तीसरे बच्चे की अनुमति देना शामिल है कि अगर एक जोड़े की दो बेटियां हैं और यह भी कि पहले दो बच्चों में से कोई भी शारीरिक रूप से विकलांग है। कई लोगों ने दो-बच्चे के मानदंड के बजाय तीन-बच्चों के मानदंड का सुझाव दिया है। यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एन. मित्तल ने कहा कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा। आयोग ने पिछले महीने अपनी वेबसाइट पर लोगों से सुझाव मांगे थे और 8,500 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए थे।

सूत्रों के अनुसार, कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। अन्य सुझावों में उन जोड़ों को आरक्षण का लाभ न देना शामिल है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और ऐसे जोड़ों को वोट देने का अधिकार रद्द करना भी शामिल है। मसौदा कानून के अनुसार, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं होंगे। जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे माता-पिता 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक बच्चे के माता-पिता को कई लाभ मिलेंगे। अगर ऐसे माता-पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें सरकारी आवास योजना में वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विभिन्न रियायतें मिलेंगी। अगर वे सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो ऐसे माता-पिता को जल कर, गृह कर, गृह ऋण और अन्य कई रियायतों में छूट मिलेगी। इसके अलावा, अगर एक बच्चे के माता-पिता पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं तो बच्चा 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और बीमा का हकदार होगा। इस बच्चे को सरकारी नौकरी में भी वरीयता मिलेगी।

प्रधानमंत्री कोरे चुनावी प्रचार से बाज आएं, गरीबों को 400 रुपये का सिलेंडर मुहैया कराएं: कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किए जाने को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि कोरेचुनावी प्रचार से बाज आना चाहिए और गरीबों को 400 रुपये का एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के उपयोग में लाए जाने वाले तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन सरकार स्वांग रचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा जिले में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उज्ज्वला योजना-दो के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऑनलाइन इस कार्यक्रम में मोदी ने उज्ज्वला योजना के पहले चरण के पांच लाभार्थियों से बातचीत भी की। सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, ''विडंबना देखिए, लोगों के घरों में महंगाई का अंधेरा परोसने वाले लोग अपनी योजनाओं का नाम उज्ज्वला रख रहे हैं। आज जब मोदी जी उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला- 2 की शुरुआत कर रहे हैं, तब देश को जानना चाहिए कि पहले उज्ज्वला के नाम पर क्या अंधेरा गरीबों के घर में परोसा गया है।'' उन्होंने यह भी कहा, ''आज खाना बनाने की गैस के दाम महोबा में 888 रुपये प्रति सिलेंडर हैजो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का हुआ करता था। नाम उसका उज्ज्वला नहीं था, मगर लोगों के घरों में गैस के सस्ते दामोंकी रोशनी जगमगा रही थी।''

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, ''उज्ज्वला गैस लेने वाले करीब आठ करोड़ परिवारों में से 3 करोड़ परिवारों ने गैस का सिलेंडर रिफ़िल ही नहीं कराया है क्योंकि वो इतनी भारी भरकम कीमत नहीं चुका सकते। ज़्यादातर लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए कि कैरोसिन की पूरी सब्सिडी भी मोदी जी ने 1 अप्रैल 2021 से समाप्त कर दी और उसके दाम दो गुना से अधिक बढ़ा दिए।'' सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, ''हमने सुना था कि जंगल की आग पर आग से काबू पाया जाता है। आज मोदी जी पेट्रोल, डीज़ल खाना बनाने की गैस ,खाने का तेल सब के दामों में आग लगाकर गरीबों के पेट की आग बुझाने का स्वांग रच रहे हैं।'' उन्होंने कहा, '' मोदी जी ,कोरे चुनावी प्रचार से बाज़ आइए, गरीबों को उज्ज्वला की गैस कांग्रेस की तरहफिर से 400 रु में मुहैया कराइए।

जाट समाज को आरक्षण देगी मोदी सरकार? किसान आंदोलन को कमजोर करने की तैयारी

लखनऊ। (एजेंसी)।

केन्द्र की मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग संविधान संशोधन विधेयक के जरिये जाट समुदाय के वोटरों को मजबूती के साथ भाजपा से जोड़ने की जुगत में लगा है।ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के बाद मोदी सरकार अगले कदम के रूप में केंद्र में जाट समाज को आरक्षण देकर किसान आंदोलन को भी कमजोर करने का इरादा रखती है। केंद्र सरकार की नजरें किसान आंदोलन पर शुरू से टेड़ी है।उसे लगता है कि नया कृषि कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हैं लागू भी नहीं हुआ है उस पर बवाल करना किसान नेताओं की सोची समझी साजिश है और इसके लिए उसे कांग्रेस जैसे दलों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

गौरतलब हो नये कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में बढ़-चढ़ कर अपनी भूमिका निभा रही जाट बिरादरी को साधने के लिए भाजपा की योजना हरियाणा में जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करने की भी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पूर्व इस बिरादरी को साधने के लिए मोदी सरकार इन्हें केंद्रीय सूची में भी शामिल कर सकती है।गौरतलब है कि जाट बिरादरी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में ओबीसी सूची में शामिल हैं। हरियाणा में इस बिरादरी को आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अलावा लंबे समय से चली आ रही मांग के बावजूद जाट बिरादरी को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी की सूची में अब तक जगह नहीं मिली है। इस संशोधन विधेयक के जरिये इसका रास्ता तैयार किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौया द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)